दैनिक तमसा संकेत

अम्बेडकर नगर व लखनऊ से एक साथ प्रकाशित
डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 06:57
सूर्यास्तः 05:31
अधिकतमः 18°00
न्यूनतमः 09°00

पेज 07

विशेष समाचार | दूषित पानी से मौतें: जवाबदेही ... >> पेज 04 | केशव मौर्य ने सपा और विपक्ष ... >> पेज 06 | तारा सुतारिया और वीर पहारिया का ...

मेरे पास शाह के खिलाफ पेन ड्राइवः ममता

मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं, ईडी की रेड के बाद कोलकाता में रैली की

प्रदर्शन

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता/नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में TMC के IT सेल के चीफ के ठिकानों पर गुरुवार को हुई ईडी रेड के विरोध में TMC दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर दो FIR भी दर्ज कराई है। उन्होंने कोलकाता में मार्च भी निकाला। इस दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव हैं। मेरे पास इसके सबूत हैं। जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं।

>> (शेष पेज 06 पर)

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सैकड़ों TMC कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए।

> ममता ने कहा, कोयला घोटाले का पैसा सुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देतीं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।

सीएम यादव बोले- ममता का ऐसी हल्की हरकत करना ठीक नहीं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से यह अपेक्षा होती है कि वह प्रवर्तन निदेशालय जैसे केंद्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करे। हम सभी शपथ इसी बात के लिए लेते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ सहयोग करेंगे। यादव ने कहा- ऐसे माहौल में यदि स्वयं मुख्यमंत्री इस तरह की हल्की हरकत करें, तो यह उचित नहीं है। एक राज्य की मुख्यमंत्री के नाते से उनका यह कृत्य कतई सही नहीं माना जा सकता।

ममता बोली- ईडी ने टीएमसी का डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश

ममता बनर्जी ने कहा कि वह कल ईडी की कार्रवाई के दौरान मौके पर गई थीं और इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान उनकी पार्टी का डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश की गई। ममता ने कहा- अगर कोई मुझ पर राजनीतिक हमला करता है, तो मैं और मजबूत होकर वापस आती हूं।

ममता की 3 बड़ी बातें

» चुनाव आयोग में बैठे एक अधिकारी पहले अमित शाह के सहयोग विभाग के सचिव रह चुके हैं। मुझे इससे निजी आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा ने हरियाणा और बिहार में जबरन सत्ता हासिल की और अब वही कोशिश बंगाल में की जा रही है।

» एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी परेशान किया गया। बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। भाजपा रोहिंग्याओं की बात करती है, लेकिन असम में रोहिंग्या हैं तो वहां एसआईआर क्यों नहीं लागू किया गया।

» ईडी ने छापेमारी के दौरान पार्टी का डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश की। मैं कल ईडी की कार्रवाई के दौरान मौके पर गई थीं और इसमें कुछ भी गलत नहीं किया।

कांग्रेस नेता बोले- टीएमसी प्रवासी मजदूरों पर हमले का विरोध नहीं करती

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि TMC सिर्फ ED की छापेमारी पर ही विरोध कर रही है, लेकिन बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर हमलों पर कभी विरोध नहीं किया। चौधरी ने कहा कि जब बंगाल के मजदूर देश के अलगअलग हिस्सों में काम करने जाते हैं और "बांग्लादेशी होने" के बहाने उन पर हमला होता है और उन्हें भागना पड़ता है।

ममता ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई

ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ईडी के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई। ये शिकायतें राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई छापों से जुड़ी हैं। इन शिकायतों के आधार पर कोलकाता और बिधाननगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के खिलाफ जितनी चाहें उतनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बंगाल के लोग बीजेपी और दिल्ली के मालिकों के सामने नहीं झुकेंगे।

इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा- गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर विरोध करना, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्हें सड़कों पर घसीटना कानून का पालन नहीं है, बल्कि यह पुलिस की घमंड दिखाने की कोशिश है। एक दिन पहले ईडी की टीम ने गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्टलेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन ही ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटजी तैयार करते हैं।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शर्मिला टैगोर के वकील

कहा- दिल्ली एम्स में मौजूद डॉग ने किसी को नहीं काटा

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं में से एक एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर इस समस्या से निपटने के लिए हाल ही में उठाए गए कदमों का विरोध किया। उनके वकील ने कहा कि सभी कुत्ते आक्रामक नहीं होते। दिल्ली एम्स में गोल्डी नाम का एक कुत्ता है, जो सालों से वहां है लेकिन कभी किसी को नहीं काटा। इस बात पर कोर्ट ने टैगोर के वकील को फटकार लगाते हुए कहा, 'क्या उस कुत्ते को हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर भी ले जाया गया है? सड़कों पर रहने वाले कुत्तों में अक्सर कीड़े-मकोड़े होते हैं और हॉस्पिटल में ऐसे संक्रमित कुत्तों की मौजूदगी से भयावह स्थिति हो सकती है।' क्या आपको इसकी समझ है? हम आपको इस बहस की वास्तविकता से अवगत कराएंगे। आप सच्चाई से बिल्कुल परे हैं और हॉस्पिटल में ऐसे कुत्तों को अच्छा दिखाने या महान साबित करने की कोशिश न करें। वहीं ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल (ACGS) संस्था की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से मौजूद हैं।

लव जिहाद का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार

18 दिन से 4 राज्यों में ढूंढ रही थी पुलिस

कार्यवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। KGMU में लव जिहाद और धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन गिरफ्तार हो गया है। उस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने उसे लखनऊ से पकड़ा है। वह ठाकुरगंज में रह रहा था, जबकि पुलिस टीमें उसकी तलाश 4 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में कर रही थीं। पुलिस ने लखनऊ, पीलीभीत और खटीमा वाले घरों पर 7 जनवरी को ही कुर्की का नोटिस चिपकाया था। 5 जनवरी को पिता सलीमुद्दीन और मां खतीजा को गिरफ्तार किया गया था। मामला 23 दिसंबर 2025 को सामने आया था, जब KGMU में एमडी पैथोलॉजी की छात्रा ने चौक थाने में शिकायत दी थी।

>> (शेष पेज 06 पर)

फास्ट न्यूज

अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी

देहरादून। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच अब CBI कर सकती है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के लिए संस्तुति प्रदान कर दी है। वहीं, सीएम धामी ने एक वीडियो जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि अंकिता के माता-पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है।

साकेत कोर्ट में स्टाफ ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया

नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में शुक्रवार को एक कर्मचारी ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें लिखा था- ऑफिस में काम के दबाव के कारण आज मैं सुसाइड कर रहा हूं। मृतक की पहचान हरीश सिंह महार के रूप में हुई है। वह साकेत कोर्ट परिसर में अहलमद (अदालती रिकॉर्ड और केस फाइलों की देखरेख करने वाला क्लर्क) के पद पर तैनात था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही उनकी टीम साकेत कोर्ट परिसर पहुंची।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बम से उड़ाने की धमकी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को गुरुवार देर रात ई-मेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। ई-मेल में राज्यपाल को बम से उड़ाने की बात लिखी थी। पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोलकाता के पास सॉल्ट लेक इलाके से पकड़ा गया है।

देश के 44% शहरों की हवा खराब

दिल्ली-गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित मेघालय का बर्नीहाट भी शामिल

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। देश के करीब 44 प्रतिशत शहर लंबे समय से एयर पॉल्यूशन का सामना कर रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) ने सैटेलाइट डेटा की मदद से देश के 4,041 शहरों में PM2.5 प्रदूषण को लेकर रिसर्च की। इसमें सामने आया है कि मेघालय का बर्नीहाट, दिल्ली और गाजियाबाद देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। इन शहरों में पॉल्यूशन की समस्या एक-दो दिन की नहीं, बल्कि सालभर बनी रहती है। पॉल्यूशन का मुख्य कारण गाड़ियों, फैक्ट्रियों और दूसरे कारणों से लगातार निकलने वाला प्रदूषण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से 2024 के बीच हर साल कम से कम 1,787 शहरों में PM2.5 का स्तर तय सीमा से ज्यादा रहा। इसमें कोविड से प्रभावित साल 2020 का डेटा नहीं लिया गया। भारत के 44 प्रतिशत शहर 'क्रॉनिक एयर पॉल्यूशन' यानी लगातार वायु प्रदूषण के कैटगरी में आते हैं।

>> (शेष पेज 06 पर)

देवरिया में दर्ज केस पर जेल में ही रहेंगे, लखनऊ पीजीआई में चल रहा इलाज

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को वाराणसी कोर्ट से जमानत

सुनवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी। वाराणसी कोर्ट से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जमानत मिल गई है। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट ने जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। इसके बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को 50-50 हजार दो जमानतदार और बंधपत्र देने पर जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि, देवरिया केस में अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है, इसलिए रिहा नहीं होंगे। फिलहाल अमिताभ ठाकुर जेल में नहीं हैं। वह अभी लखनऊ PGI में इलाज करा रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी नेता और बड़ी पियरी निवासी अंबरीश सिंह भोला ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

>> (शेष पेज 06 पर)

23 दिसंबर को जमानत अर्जी दाखिल की गई थी

अमिताभ ठाकुर की ओर से 23 दिसंबर को वाराणसी की जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। हालांकि, बनारस बार एसोसिएशन चुनाव के कारण सुनवाई टल गई थी। आज इसी अर्जी पर अमिताभ ठाकुर को जमानत मिली।

आजाद अधिकार सेना ने अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को बताया अवैध

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय, देवरिया में एक याचिका दायर की गई है। आजाद अधिकार सेना की ओर से सिंहासन चौहान ने यह याचिका दाखिल की है। इसमें यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) सहित छह अधिकारियों को नामजद किया गया है। इसमें मांग की गई है कि थाना कोतवाली, देवरिया को निर्देशित किया जाए कि वह नामजद अधिकारियों- आईपीएस अमिताभ यश, आईपीएस अमरेंद्र सेंगर, डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर विनीत सिंह, एसीपी कुलदीप दुबे और अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराए। इससे उनकी छवि धूमिल हुई, जिसके चलते एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई। अदालत द्वारा मामले में वारंट 'बी' जारी होने के बाद पुलिस ने 19 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से लाकर प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय की अदालत में पेश किया था। जमानत अर्जी पर सुनवाई नही हो सकी थी।

विवाद : लेकिन हर समस्या के लिए उन्हें अकेले दोषी ठहराना गलत, मोदी सरकार उनकी विरोधी

नेहरू की गलतियां स्वीकार करना जरूरीः थरूर

तमसा संकेत, एजेंसी

तिरुवनंतपुरम/कोच्चि। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि नेहरू की गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन देश की हर समस्या के लिए उन्हें अकेले दोषी ठहराना पूरी तरह गलत और अनुचित है। थरूर ने कहा- मैं यह नहीं कहूंगा कि मोदी सरकार लोकतंत्र-विरोधी है, लेकिन वे निश्चित रूप से नेहरू-विरोधी हैं। नेहरू को एक सुविधाजनक बलि का बकरा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों और दृष्टिकोण की गहरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन नेहरू की हर मान्यता और नीति का बिना आलोचना समर्थन नहीं कर सकता। थरूर गुरुवार को केरल विधानसभा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव (KLIBF) के चौथे संस्करण में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि नेहरू भारतीय लोकतंत्र के संस्थापक थे। उन्होंने इसे मजबूती से स्थापित किया। उन्होंने बताया कि 1989 में The Great Indian Novel इसलिए लिखा क्योंकि उस समय भारत में व्यंग्य विधा लगभग न के बराबर थी। युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए थरूर ने कहा कि आज के दौर में कम पन्नों वाली छोटी किताबें ज्यादा प्रभावी हो सकती हैं, क्योंकि लोगों के पास पढ़ने के लिए समय कम होता जा रहा है।

अस्थमा, लिखने-पढ़ने की आदत का जिक्र

अपने लेखक जीवन की चर्चा करते हुए थरूर ने कहा कि बचपन में अस्थमा की बीमारी के कारण उनका झुकाव किताबों की ओर हुआ। उस समय न तो टेलीविजन था और न ही मोबाइल फोन, इसलिए किताबें ही उनकी सबसे करीबी साथी बन गईं। उन्होंने बताया कि उनका पहला उपन्यास बहुत कम उम्र में लिखा गया था, लेकिन स्याही गिरने के कारण वह नष्ट हो गया। श्री नारायना गुरू की जीवनी उनकी 28वीं पुस्तक है। दुनिया के कई हिस्सों में पढ़ने की आदत घट रही है, लेकिन केरल आज भी पढ़ने की संस्कृति में अग्रणी बना हुआ है।

27 दिसंबर- प्रधानमंत्री का हारना भारत के हारने जैसा

विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं, भारत की होती है। अगर राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है, तो वह भारत की हार की खुशी मना रहा होता है। भारत को पाकिस्तान से आने वाले सुरक्षा खतरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से

शीतकालीन सत्र में वीबी-जी राम जी बिल सहित 8 बिल पास हुए

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी (रविवार) को पेश किया जाएगा। सत्र दो चरणों में होगा। पहला चरण 13 फरवरी को खत्म होगा। इसके बाद सत्र की कार्रवाई 9 मार्च से दोबारा शुरू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 28 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का पारंपरिक संबोधन साल के पहले संसद सत्र के पहले दिन होता है। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते संसद स्थगित रहेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। संसद में 30 जनवरी को बैठक करेगी। उस दिन इकॉनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी। राष्ट्रपति के संबोधन और केंद्रीय बजट पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद, संसद 13 फरवरी से लगभग एक महीने की अवकाश अवधि के लिए स्थगित होगी। संसद 9 मार्च को पुनः बैठक करेगी और सत्र 2 अप्रैल, गुरुवार को समाप्त होगा।

>> (शेष पेज 06 पर)

दरवाजे की सिटकनी-गमले तोड़े, मुकदमा होगा, बोलीं- धर्मांतरण पर केजीएमयू सख्त नहीं

अपर्णा यादव के समर्थकों ने मचाया उत्पात

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ के KGMU में लव जिहाद प्रकरण चल रहा है। इसी बीच शुक्रवार को अपर्णा यादव KGMU में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गईं। उनके साथ करीब 25-30 समर्थक और कार्यकर्ता भी थे। अपर्णा वहां पहुंचीं, तो VC चैंबर बंद था। यह देखते ही अपर्णा यादव के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। चैंबर के दरवाजे को कई लोग मिलकर धक्का देने लगे, जिससे उसकी सिटकनी टूट गई। हंगामे के दौरान गमला भी टूट गया। VC चैंबर का कंप्यूटर गिर गया। इस उत्पात के बाद अपर्णा यादव ने KGMU परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा- KGMU प्रशासन लव जिहाद, धर्मांतरण पर सख्त नहीं है। अपर्णा यादव यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं।

हंगामा

कुलपति ने कहा- आयोग उपाध्यक्ष के सभी आरोप निराधार

KGMU की कुलपति सोनिया नित्यानंद ने कहा कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव यहां आएंगी, इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। यह बहुत गलत हुआ। इस तरह से यूनिवर्सिटी में ऐसी घटनाओं को नहीं होना चाहिए। अपर्णा यादव के सभी आरोप निराधार हैं। प्रवक्ता केके सिंह का कहना है कि मामले में जब सीएम ऑफिस और राज्यपाल को अवगत कराया गया तो इसके बाद कुलपति ऑफिस में लोग शांत हुए और यहां से बाहर गए। अगर हमारा शिक्षक असुरक्षित हो जाता है तो हम लोगों को यहां पर रहने पर कोई फायदा नहीं है। लव जिहाद का प्रकरण दोबारा ना हो इस सवाल के जवाब में केके सिंह ने कहा कि यहां पर जो लोग आते हुए वह टॉप इंटलेक्चुअल होते हैं।

केजीएमयू में दिसंबर, 2025 में उठा लव जिहाद प्रकरण

KGMU में दिसंबर, 2025 में लव जिहाद प्रकरण उठा था। इसमें एक पीड़िता ने रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक पर धोखे में फंसाने, प्रेग्नेंट करने और अबॉर्शन कराने के साथ ही जबरदस्ती धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। पीड़िता सीएम योगी से मिली थी और म हिल ा आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई थी।

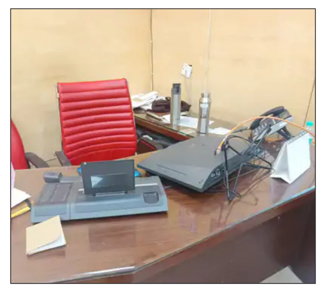
VC चैंबर के कंप्यूटर के मॉनिटर गिर गए। हंगामे के बाद कई जगह इसी तरह के हालात हो गए।

वीसी बोलीं- ऐसे माहौल में काम करना नामुमकिन है

कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने अपर्णा यादव के समर्थकों के साथ घुसने और ऐसी घटना होने पर कहा कि ऐसे माहौल में काम करना संभव नहीं है। KGMU परिवार पीस मार्च निकालेगा और जरूरत पड़ी तो बायकॉट भी करेगा।

अपर्णा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने KGMU पर जमकर सवाल उठाए।

स्पा सेंटर में लगी आग, सामान जलकर राख

फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 30 मिनट में आग पर पाया काबू

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ सुशांत गोल्ड सिटी स्थित मिलेनियम पैलेस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर स्पा सेंटर में आग लग गई है। आग लगने से सैलून का पूरा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 30 मिनट में आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्टकट बताया जा रहा है। एफएसओ माम चंद बड़गुर्जर ने बताया कि देर रात करीब 2:00 बजे कंट्रोल रूम पर आग लगने की सूचना आई। कॉलर ने बताया कि सुशांत गोल्फ सिटी अंतर्गत मिलेनियम पैलेस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर संचालित ADS SPA AND SALOON में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर टैंकर मौके पर भेजे गए। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि स्पा सेंटर के अंदर

आग लगी हुई थी। वहां मौजूद लोग अग्निशमन उपकरणों की सहायता से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। आगे की लपटे तेज होने के कारण वो लोग आग बुझा नहीं पाए। दुकान के अंदर धुआं भरा हुआ था। जिसके चलते सबसे पहले धुआं बाहर निकाला गया। इसके बाद फायर सर्विस यूनिट की मदद से आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जिसमें करीब 30 मिनट में आज पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। आग स्पा सेंटर के मसाज रूम में लगी थी। घटना के समय दुकान मालिक धनंजय मौके पर मौजूद थे।

फास्ट न्यूज

कुत्ते को दौड़ाकर गोली मारी

दुबग्गा। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर के बाहर खेल रहे कुत्ते पर सरेआम फायरिंग कर दी। इस घटना में कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पशु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग के समय घटनास्थल के पास कई बच्चे मौजूद थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। शिकायत-कर्ता ने बताया कि फायरिंग के दौरान कई बच्चे पास में खेल रहे थे। गोली किसी बच्चे को भी लग सकती थी।

एसआईआर में सपा विधायक के भाई-भतीजे के नाम गायब

लखनऊ। SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची ने लखनऊ की राजनीतिक तस्वीर बदलती दिख रही है। जिले में 12 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं। प्रदेश में सबसे अधिक वोट लखनऊ में ही कटे हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा क्षेत्र के उत्तर विधान सभा क्षेत्र शामिल है। यहां 1.91 लाख वोटर कम हुए हैं। राजधानी में बड़ी संख्या में वोट कटने से सभी 9 विधानसभा और दोनों लोकसभा सीटों के चुनावी समीकरण बदलने की संभावना है।

महिला का अर्धनग्न शव मिला, हत्या की आशंका

सरोजनी नगर, लखनऊ। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक अज्ञात अधेड़ महिला का अर्धनग्न शव मिला। शव नरायनपुर-फतेहगंज रोड किनारे अमावा जंगल में एक पुलिया के पास सुनसान जगह पर पड़ा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर बंथरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतका की उम्र लगभग 50 वर्ष आंकी जा रही है। उसके चेहरे और माथे पर चोट के निशान थे।

युवक की हत्या कर शव जलाया

50% झुलसी बॉडी झाड़ियों में पड़ी मिली

तमसा संकेत, एजेंसी

मोहनलालगंज। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में शुक्रवार को एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। अलखनंदा पुलिस चौकी क्षेत्र के भागीरथी एनक्लेव के पास सड़क किनारे झाड़ियों में शव बरामद हुआ। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है। शव को किसी चादर में बांधकर लाया गया था और फिर आग लगाकर जलाने का प्रयास किया गया, जिससे यह करीब 50 प्रतिशत तक जल चुका था। घटना की गंभीरता को देखते हुए फील्ड

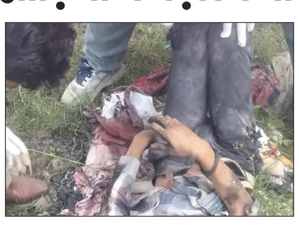

यूनिट और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीमों ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और तकनीकी माध्यमों से संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मामले के शीघ्र खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें गठित की हैं। शव का पंचायतनामा भरकर उसे मॉर्च्युरी हाउस में सुरक्षित रखवा दिया गया है।

25 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा, मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी

रिटायर्ड बैंकर से 2.75 करोड़ की ठगी

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में साइबर ठगों ने एक 68 साल के रिटायर्ड बैंकर को डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 75 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को ट्राई, पुलिस और कोर्ट का अधिकारी बताकर करीब 25 दिनों तक साइबर रिमांड में रखा। पीड़ित सिद्धार्थ नाथ (68) एक सेवानिवृत्त बैंकर हैं। उन्होंने थाना विकास नगर में प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद कॉल को दूसरे नंबर पर ट्रांसफर कर दिया गया, जहां आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि पीड़ित के आधार कार्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज है। पीड़ित को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने का नाटक किया गया। फर्जी जज और वकीलों के जरिए बताया गया कि उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और फोन सर्विलांस पर है। ठगों ने कहा कि जांच के दौरान खाते में मौजूद रकम कोर्ट के आदेश पर सुरक्षित खातों में जमा करानी होगी।

एक कॉल से शुरू हुआ खेल

30 अगस्त 2025 को पीड़ित के मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या उन्होंने मुंबई में एक सिम कार्ड खरीदा है। मना करने पर कहा गया कि उस सिम से गैरकानूनी गतिविधियां हो रही हैं और ट्राई को शिकायत मिली है।

एफडी, शेयर, म्यूचुअल फंड सब खाली

डर और मानसिक दबाव में आकर पीड़ित ने अपने एफडी, शेयर और म्यूचुअल फंड तुड़वाए। अलग-अलग तारीखों में PNB सहित कई बैंकों से 2.75 करोड़ रुपए विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। डर और मानसिक दबाव में आकर पीड़ित ने अपने एफडी, शेयर और म्यूचुअल फंड तुड़वाए। डर और मानसिक दबाव में आकर पीड़ित ने अपने एफडी, शेयर और म्यूचुअल फंड तुड़वाए।

जमानत के नाम पर और 50 लाख मांगे

24 सितंबर को ठगों ने कहा कि कोर्ट जमानत देने को तैयार है, जब पीड़ित असमर्थ रहे तो आरोपियों ने कॉल उठाना बंद कर दिया। तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

> पीड़ित ने बताया कि यह रकम उनकी और उनकी दिवंगत पत्नी की पूरी जीवनभर की कमाई थी। इस घटना के बाद वे गहरे सदमे में हैं और मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं। पीड़ित ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में गंभीर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की जाए। सभी संदिग्ध खातों को तुरंत फ्रीज कराया जाए। मामला साइबर क्राइम सेल को सौंपकर रकम की रिकवरी कराई जाए।

स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की टीम ने महिला अस्पताल का किया निरीक्षण

वीरांगना अवंती बाई महिला अस्पताल में एफआरयू सुविधाओं की गहन जांच

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ/बंथरा। थाना बंथरा क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर–बेहटा मार्ग पर ग्राम अमावा के सामने शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव पड़ा मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। महिला की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई।सूचना मिलते ही थाना बंथरा पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू की। पुलिस द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतका संभवतः भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन-यापन करती थी। महिला के पास मिले बैग से शराब

के पाउच, बीड़ी, कपड़े और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद हुई हैं, जिससे इस आशंका को बल मिला है।घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए, ताकि मृत्यु के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। अभी तक की जांच में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा है कि महिला की मौत किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई है, हालांकि पुलिस ने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही है।पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका की शिनाख्त न हो पाने के कारण आसपास के थाना क्षेत्रों में सूचना भेजी गई है और स्थानीय लोगों से भी पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यदि महिला की पहचान हो जाती है तो उसके परिजनों को सूचना देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना बंथरा पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है।

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण: 4.61 लाख आवास आवंटित, 3.65 लाख का निर्माण पूरा

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन में योजना क्रियान्वित

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन और निर्देशन में दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ विभिन्न सरकारी और अर्धसरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा रचनात्मक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उनकी दक्षता और क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इस कड़ी में संस्थान द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5 से 7 जनवरी 2026 तक ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ₹थीम ऑफ स्टेट बजट₹ विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय

और राज्य ग्राम्य विकास संस्थानों के अधिकारियों के लिए संपन्न हुआ। वहीं, 5 से 10 जनवरी तक क्षमता निर्माण विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम खंड विकास अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, 5 से 10 जनवरी तक हास्पीटल आपदा प्रबंधन एवं योजना निर्माण विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम मेडिकल चिकित्सकों, राजस्व अधिकारियों एवं अग्निशमन अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। इसी अवधि में ₹इन्नोवेटिव वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स₹ विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम उड़ीसा के पशुधन प्रसार अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। 7 जनवरी को बेविनार कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें महानिदेशक संस्थान

एल० वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में मिशन कर्मयोगी विषयक व्याख्यान आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ० किशन वीर सिंह शाक्य, प्रख्यात शिक्षाविद् एवं पूर्व वरिष्ठ सदस्य लोक सेवा आयोग, डॉ० पी. के. मिश्रा, संयुक्त निदेशक, एफ. ए. आर. डी, उड़ीसा, प्रोफेसर डॉ० आर. रमेश, एनआईआरडी, हैदराबाद और डॉ० लाखन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनआईआरडी, हैदराबाद विशिष्ट अतिथि वार्ताकार के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों पर विस्तृत और प्रासंगिक व्याख्यान दिए गए। डॉ० किशन वीर सिंह शाक्य ने प्रतिभागियों को साफ्ट स्किल्स और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान किया।

जानकारी: केजीएमयू कुलपति का डीजीएमई को लेटर, कहा- रमीज विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं रह सकता

लव जिहाद का आरोपी डॉक्टर निष्कासित होगा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। KGMU यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी डॉ. रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक को निष्कासित करेगा। कुलपति सोनिया नित्यानंद ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। विशाखा कमेटी की रिपोर्ट पर यह एक्शन लिया गया है। DGME भी मामले में कार्रवाई करेगा। KGMU के ब्राउन हॉल में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुलपति ने आरोपी डॉ. रमीज मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में रमीज मलिक अब KGMU का हिस्सा नहीं रह सकता। यही कारण है कि अब यूनिवर्सिटी ने कठोरतम कार्रवाई की संस्तुति की है। इसके लिए विशाखा कमेटी के रिपोर्ट के आधार DGME को आज लेटर लिखा जा रहा जा है। बहुत जल्द उसे निष्कासित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले 22 दिसंबर को ही उसे सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद से ही कैंपस में उसकी एंट्री बैन है। पत्रकार वार्ता के दौरान विशाखा कमेटी की प्रमुख और KGMU के एनेस्थीसिया विभाग की HOD डॉ. मोनिका कोहली ने कहा कि जांच कमेटी के सामने महज एक बार रमीज पेश हुआ था। उसने तब ये कहा था कि दोनों ने आपसी रजामंदी से संबंध बनाए थे। उसने पहले से शादीशुदा होने की बात को नकार दिया था। मोनिका कोहली ने कहा कि जांच में आरोपी को दोषी पाया गया। इसके बाद सभी सदस्यों की सहमति से फाइनल रिपोर्ट कुलपति को भेज दी गयी। अब आगे की कार्रवाई कुलपति के द्वारा की जाएगी।

सभी विभागों में इकट्ठा किए जा रहे धर्मांतरण के इनपुट

KGMU प्रवक्ता डॉ. के.के. सिंह ने बताया कि 7 सदस्यीय कमेटी पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। अब KGMU का कोई भी व्यक्ति परिसर के अंदर धर्मांतरण या इसके प्रयास से जुड़ा इनपुट बिना नाम बताए दे सकता है। इसके लिए एक ईमेल आईडी factfindingcommittee@gmcindia.edu पहले ही जारी कर दी गई थी।

7 सदस्यीय टीम कर रही जांच

धर्मांतरण और कट्टरपंथी गतिविधियों की जांच के लिए एक सात सदस्यीय टीम अलग से जांच कर रही है। उसमें पूर्व पुलिस महानिदेश भावेश भी शामिल हैं। समिति ने बुधवार को करीब ढाई घंटे तक बैठक की थी। डीन एकेडमिक ऑफिस में हुई इस बैठक में जांच कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान कुछ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स के बयान दर्ज हुए। इसके अलावा सामाजिक संगठनों से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हुए।

डॉ. रमीज फरार है। उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।

विधवा महिला को नशीला ड्रिंक पिलाकर किया रेप

फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया, रुपए ऐंठे, धमकी दी

तमसा संकेत, एजेंसी

मोहनलालगंज। निगोहां थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विधवा महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता वर्तमान में पीजीआई थाना क्षेत्र में किराए पर रह रही थी। आरोपित द्वारा की गई घटनाएं भी पीजीआई थाना क्षेत्र में ही हुई है। आरोप है कि युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर महिला से रेप किया। अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण व पैसों की वसूली करता रहा। पीड़िता के अनुसार, उसके पति की चार वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। आर्थिक तंगी के चलते वह पिछले दो वर्षों से अपनी मां और पांच वर्षीय बेटी के साथ पीजीआई

थाना क्षेत्र में किराए पर रहकर घरों में काम कर जीवनयापन कर रही थी। करीब दो महीने पहले उसने ईश्वरी खेड़ा स्थित पाल डेयरी के मालिक अंकित पाल के मकान में किराए पर एक कमरा लिया था। आरोप है कि 11 दिसंबर को अंकित के भाई का तिलक समारोह था, जिसमें पीड़िता शामिल हुई। रात करीब नौ बजे वह अपने कमरे में लौट आई। कुछ देर बाद अंकित एक महिला के साथ उसके कमरे में आया और कॉफी व खाना देते हुए खाने के लिए कहा। कॉफी और खाना खाने के बाद पीड़िता अचेत हो गई। इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ रेप किया और उसके कपड़े उतारकर अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए। अगले दिन होश में आने पर पीड़िता के शरीर पर खरोंच के निशान थे। आरोप है कि घटना के समय उसकी मां और बेटी गांव गई हुई थी। आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर पूरी रात रेप किया। इसके बाद आरोपी ने फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरन कई बार रेप किया और उससे पैसे भी वसूलता रहा। पीड़िता ने बताया कि परेशान होकर उसने 2 जनवरी को वह कमरा छोड़ दिया और दूसरी जगह रहने लगी।

अकबरपुर के बीएन इंटर कॉलेज में उमड़ी भीड़, धार्मिक सुरक्षा और संगठन पर रहा फोकस

विराट हिन्दू सम्मेलन में एकजुटता और सामाजिक मुद्दों पर मंथन

आयोजन

तमसा संकेत, संवाददाता

अम्बेडकरनगर।अकबरपुर स्थित बीएन इंटर कॉलेज परिसर में विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सम्मेलन का उद्देश्य हिन्दू समाज की एकता, सामाजिक समरसता और धार्मिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करना रहा। कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर लोगों से भरा रहा और व्यवस्था को लेकर आयोजकों की सक्रियता नजर आई।

उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि हिन्दू समाज को जाति और वर्ग के आधार पर विभाजित करने के प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे प्रयासों से समाज कमजोर होता है, इसलिए सभी वर्गों को आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने की आवश्यकता है। सम्मेलन में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख लोग शामिल हुए।

प्रमुख वक्ता ने सामाजिक जिम्मेदारियों पर रखा पक्ष

सम्मेलन के प्रमुख वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्रचारक अनिल रहे। उन्होंने अपने संबोधन में समाज के संगठित स्वरूप पर जोर देते हुए कहा कि सामाजिक एकता किसी भी समुदाय की सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने कहा कि जब समाज संगठित रहता है, तभी अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा संभव हो पाती है।

हिन्दू एकता को बताया समय की जरूरत

वक्ताओं ने कहा कि हिन्दू समाज की एकता ही सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक संरक्षण का आधार है। सम्मेलन में यह बात प्रमुखता से उभरी कि समाज को आपसी सहयोग, संवाद और संगठन की भावना के साथ आगे बढ़ना होगा।

धार्मिक सुरक्षा और सामाजिक सतर्कता पर जोर

सम्मेलन के दौरान धार्मिक सुरक्षा को लेकर भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। प्रमुख वक्ता ने कहा कि सामाजिक स्तर पर जागरूकता और सतर्कता जरूरी है। उन्होंने लव जिहाद के विषय को गंभीर सामाजिक मुद्दा बताते हुए कहा कि यह अब केवल सीमित क्षेत्रों तक नहीं रहा, बल्कि देश के अनेक जिलों में चर्चा और चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने परिवार और समाज को इस विषय पर सजग रहने की आवश्यकता बताई।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग सह प्रचारक शैलेन्द्र और हर्षवर्धन सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे। आयोजन की व्यवस्था, अनुशासन और संचालन में स्वयंसेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सम्मेलन के दौरान मंच संचालन और कार्यक्रम की समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया गया।

50 दिन से लापता बच्चा, परिजनों का धरना जारी

प्रशासनिक कार्रवाई न होने से बढ़ा जनआक्रोश

तमसा संकेत, संवाददाता

अम्बेडकरनगर। जनपद के विधानसभा क्षेत्र आलापुर अंतर्गत ग्राम सभा सरफुद्दीनपुर, पोस्ट चहोड़ा घाट निवासी हिमांशु विश्वकर्मा (पुत्र सूर्यभान विश्वकर्मा) के लापता हुए 50 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक बच्चे का कोई सुराग न लगने से परिजन और ग्रामीणों में गहरा असंतोष व्याप्त है। इसी को लेकर परिजनों द्वारा लगातार धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है, जो शुक्रवार को 50वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर समाजसेवी अंश मिश्रा और मंगल मणि तिवारी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मामले में सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। जब तक बच्चा सुरक्षित वापस नहीं आता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

धरने के दौरान समाजसेवी अंश मिश्रा ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 50 दिन बीत जाने के बावजूद ठोस कार्रवाई का अभाव गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही बच्चे का पता नहीं लगाया गया तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। पीड़ित परिवार की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। बच्चे की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि वह दो बार मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में अपनी बात रख चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।

फास्ट न्यूज

अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर युवती को परिवार से मिलाया गया

अम्बेडकरनगर। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर 8 जनवरी 2025 को जीआरपी ने 23 वर्षीय युवती को उसके परिवार से मिलाया। युवती अपने घर वालों से नाराज होकर ट्रेन से अकबरपुर स्टेशन पहुंची थी। युवती ने अपना नाम रंजना, पिता स्वर्गीय चंद्रशेखर, निवासी कुकुड़ीपुर, थाना सरायख्वाजा, जनपद जौनपुर बताया।

झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से ट्रक चालक की मौत

अम्बेडकरनगर। अम्बेडकरनगर जिले के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में राजेसुल्तानपुर बाजार स्थित चंद्रापाली क्लीनिक में झोलाछाप डॉक्टर की कथित लापरवाही से एक ट्रक चालक की मौत हो गई। यह घटना स्वास्थ्य सुरक्षा और अवैध चिकित्सा प्रथाओं पर सवाल खड़ा कर रही है। बीती गुरुवार की रात इटावा जनपद के भरथना तहसील क्षेत्र निवासी ट्रक चालक राम राकेश यादव (55 वर्ष) की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अपने वाहन को खड़ा कर इलाज के लिए वह राजेसुल्तानपुर बाजार स्थित चंद्रापाली क्लीनिक पहुंचे।

2026 में 19 जनवरी को मंच पर आएंगे कुमार विश्वास

अम्बेडकरनगर। 18 से 20 जनवरी तक श्रवण धाम में आयोजित तीन दिवसीय महोत्सव "श्रवण धाम महोत्सव–2026" को लेकर तैयारियां जोर–शोर से चल रही हैं। कुमार विश्वास की उपस्थिति महोत्सव में चार चांद लगाने वाली है। श्रवण धाम महोत्सव में न सिर्फ कविता और साहित्यिक सत्र होंगे, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत प्रस्तुति और हस्तकला प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

नारायण फाउंडेशन के कार्यों की क्षेत्र प्रचारक ने की सराहना

अम्बेडकरनगर आगमन पर हुआ औपचारिक अभिनंदन

तमसा संकेत, संवाददाता

अम्बेडकरनगर। नारायण फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश मौर्य ने शुक्रवार को अम्बेडकरनगर आगमन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्रचारक अनिल का विधिवत अभिनंदन किया। इस अवसर पर फाउंडेशन की ओर से किए जा रहे सामाजिक, शैक्षिक और सेवा से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। भेंट के दौरान दिनेश मौर्य ने बताया कि नारायण फाउंडेशन जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग की सहायता, सामाजिक जागरूकता और सेवा कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित कर रहा है। उन्होंने फाउंडेशन की अब तक की प्रमुख गतिविधियों, जनसहयोग से संचालित अभियानों और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। क्षेत्र प्रचारक अनिल

ने नारायण फाउंडेशन द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों की भूमिका समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने फाउंडेशन को अपने सेवा कार्यों को निरंतर, व्यवस्थित और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा कार्यों में पारदर्शिता, निरंतरता और समाज के प्रति समर्पण आवश्यक है। ऐसे प्रयास सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनते हैं।

स्कूल वाहनों की फिटनेस, नो हेलमेटझनो फ्यूल और हाईवे पेट्रोलिंग पर फोकस

सड़क सुरक्षा पर प्रशासन सख्त, डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

तमसा संकेत, संवाददाता

अम्बेडकरनगर। जनपद में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक अभिजित आर शंकर भी मौजूद रहे। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात नियमों के कड़ाई से अनुपालन और आपातकालीन सेवाओं की तत्परता जैसे मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की गई। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए गोल्डन आवर की अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष

जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही घायलों को निकटतम चिकित्सालय तक पहुंचाने में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शहरी क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए सभी नगर निकायों को प्रमुख चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम को क्रियाशील कराने के निर्देश दिए गए। जहां आवश्यकता हो, वहां नए सिस्टम स्थापित कराने को भी कहा गया।

स्कूल वाहनों की अनिवार्य फिटनेस जांच के निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने एआरटीओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में संचालित सभी स्कूल वाहनों की अनिवार्य रूप से फिटनेस जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। बिना मानक पूरे किए कोई भी स्कूल वाहन सड़क पर संचालित न हो।

पेट्रोल पंपों पर 'नो हेलमेट -नो फ्यूल' का सख्त अनुपालन

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिलाधिकारी ने पेट्रोल पंपों पर 'नो हेलमेट–नो फ्यूल' व्यवस्था को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए। संबंधित विभागों को कहा गया कि इस नियम का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट पहनने को लेकर जागरूकता और अनुशासन बढ़े।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित पेट्रोलिंग और एंबुलेंस की उपलब्धता

बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मानकों के अनुरूप वाहनों की नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में एंबुलेंस की उपलब्धता, मेडिकल सुविधाएं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं हर समय सक्रिय रखी जाएं।

हाईवे पर अवैध कटों पर कार्रवाई के निर्देश

बैठक में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर बने अवैध कटों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संबंधित विभागों को ऐसे अवैध कटों की पहचान कर उन्हें बंद कराने के निर्देश दिए। कारण बनते हैं और इन्हें हटाना प्राथमिकता में शामिल किया जाए।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बीएनकेबी पीजी कॉलेज अकबरपुर में छात्रों को बताए गए सड़क सुरक्षा नियम

तमसा संकेत, संवाददाता

अम्बेडकरनगर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत शुक्रवार को बीएनकेबी पीजी कॉलेज, अकबरपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और जीरो फैटेलिटी समाधान को लेकर युवाओं व आमजन को जागरूक करना रहा। आयोजन रोड सेफ्टी क्लब के संयोजन में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ एनसीसी, एनएसएस और रोवर्स-रेंजर से जुड़े स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों के पालन, सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार और दुर्घटना के बाद त्वरित सहायता के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। विशेष रूप से "राह

वीर योजना" के बारे में छात्रों को अवगत कराया गया, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को 25 हजार रुपये का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने का प्रावधान है। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज की प्राचार्य शुचिता पाण्डेय ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसका प्रमुख कारण यातायात नियमों की अनदेखी है। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सभी को नियमों का पालन करना चाहिए और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। उन्होंने युवाओं से सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। जागरूकता अभियान के दौरान छात्र-छात्राओं ने हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाने, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, ओवरस्पीड से बचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में एनसीसी के लेफ्टिनेंट विवेक तिवारी, एनएसएस प्रभारी दिनेश कुमार, रोवर-रेंजर प्रभारी अमित और सुमित्रा पटेल सहित अन्य शिक्षकों ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग यदि सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक हो जाए तो दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

प्रशिक्षण व्यवस्था और समस्याओं पर लिया गया फीडबैक

आरटीसी प्रशिक्षकों के साथ अपर पुलिस अधीक्षक की बैठक

बैठक में यह भी कहा गया कि प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रशिक्षण व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित स्तर पर प्रस्ताव भेजे जाएंगे ताकि प्रशिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

तमसा संकेत, संवाददाता

अम्बेडकरनगर। शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्याम देव द्वारा आरटीसी के आउटडोर और इंडोर प्रशिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक का उद्देश्य प्रशिक्षण की वर्तमान स्थिति, व्यवस्थाओं और प्रशिक्षकों को आ रही समस्याओं की जानकारी लेना रहा। बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने आरटीसी में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अनुशासन, संसाधनों की उपलब्धता और प्रशिक्षण के दौरान आने वाली

व्यावहारिक दिक्कतों के बारे में जानकारी ली। प्रशिक्षकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए प्रशिक्षण से जुड़ी आवश्यकताओं और समस्याओं से अवगत कराया। इंडोर प्रशिक्षण से जुड़े प्रशिक्षकों ने कक्षा संचालन, पाठ्य सामग्री, तकनीकी संसाधन और समय प्रबंधन से संबंधित विषयों पर चर्चा की। वहीं आउटडोर प्रशिक्षकों ने फील्ड ट्रेनिंग, शारीरिक अभ्यास, परेड, हथियार प्रशिक्षण और मैदान से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक प्रस्तुत किया। प्रशिक्षकों ने कुछ बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता भी बताई। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षकों को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, समयबद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण का स्तर जितना बेहतर होगा, उतनी ही प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रशिक्षकों से अपेक्षा की गई कि वे प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक और आधुनिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करें। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। अंत में अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रशिक्षकों से नियमित संवाद बनाए रखने और प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी समस्या को समय रहते अवगत कराने की बात कही।

बैठक : 18 से 20 जनवरी तक प्रस्तावित महोत्सव को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने पर प्रशासन का फोकस

श्रवण धाम महोत्सव -2026 की तैयारियों की समीक्षा

तमसा संकेत, संवाददाता

अम्बेडकरनगर। जनपद अम्बेडकरनगर में 18 से 20 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित तीन दिवसीय श्रवण धाम महोत्सव–2026 की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला भी उपस्थित रहे। बैठक में महोत्सव के सफल आयोजन के लिए गठित 25 समितियों के नोडल और सह-नोडल अधिकारियों के साथ तैयारियों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सौंपे गए दायित्वों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि महोत्सव की प्रत्येक व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी समितियों को कार्यों की अद्यतन स्थिति समय-समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक उपचार केंद्र, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अग्निशमन विभाग को अस्थायी फायर पोस्ट, उपकरण और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा की गई। महोत्सव के दौरान मीडिया समन्वय, सूचना प्रसार और अतिथियों के आवास, स्वागत व आवागमन की व्यवस्थाओं को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोजन से जुड़ी सभी सूचनाएं समय पर और व्यवस्थित ढंग से साझा की जाएं, जिससे किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। समीक्षा बैठक में यह भी कहा गया कि श्रवण धाम महोत्सव जनपद की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान को सशक्त करेगा।

कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर सख्त निर्देश

महोत्सव के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने को कहा गया। पार्किंग स्थलों की पहचान, डायवर्जन प्लान और आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर भी जोर दिया गया।

व्यवस्थाओं पर विशेष जोर, श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि

बैठक में मंच व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, अस्थायी शौचालय, अलाव, प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, एंबुलेंस व्यवस्था, अग्निशमन, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा प्रबंध, यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं और आगंतुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका हर स्तर पर ध्यान रखा जाए।

संगठन से लेकर सियासत तक साधे कई लक्ष्य

कमजोर भाजपा संगठन के बीच संघ ने संभाला मोर्चा

तमसा संकेत, संवाददाता

अम्बेडकरनगर। अकबरपुर में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर जनपद की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह आयोजन केवल धार्मिक या सामाजिक दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रणनीतिक सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों की मानें तो संघ ने इस सम्मेलन के माध्यम से एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। लंबे समय से जनपद में भाजपा संगठन को लेकर यह धारणा बनी हुई है कि संगठनात्मक मजबूती और जमीनी सक्रियता में कमी है। कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता, कार्यक्रमों की कमी और

आपसी तालमेल का अभाव स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। ऐसे माहौल में हिंदू सम्मेलन को संघ की उस पहल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके जरिए सामाजिक आधार को फिर से सक्रिय किया गया। बीएन इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि संघ के पास अब भी भीड़ जुटाने और समाज को संगठित करने की क्षमता है। मंच से हिंदू एकता, जातिगत विभाजन, धार्मिक सुरक्षा और सामाजिक सतर्कता जैसे मुद्दों पर जो बातें रखी गईं, उन्हें वैचारिक के साथ-साथ संगठनात्मक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। सम्मेलन की तैयारियों से लेकर संचालन तक संघ से जुड़े स्वयंसेवक पूरी तरह सक्रिय नजर आए। वहीं, भाजपा से जुड़े कई नेता मंच पर मौजूद रहे, लेकिन संगठन के स्तर पर नेतृत्व और दिशा देने की भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई दी। राजनीतिक हलकों में इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि संघ ने संगठनात्मक खालीपन को भरने की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है।

सम्पादकीय

अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा

नेशनल मेडिकल कमीशन ने मंगलवार देर रात जम्मू-कश्मीर के रियासी में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द कर दी नेशनल मेडिकल कमीशन ने मंगलवार देर रात जम्मू-कश्मीर के रियासी में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द कर दी। इस खबर को पढ़ते ही शौक़ बहराइची का मशहूर शेर याद आ गया कि- देश में पहले से अच्छे उच्च शिक्षा संस्थानों की भारी कमी है। धार्मिक स्थलों के निर्माण, सौंदर्यीकरण, रख-रखाव पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, सरकार में बैठे लोगों का रोजमर्रा का खर्च लाखों में होता है, फिजूल के प्रचार कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन जब उच्च कोटि के अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों के निर्माण और उन्नयन की बारी आती है तो सरकार के पास धन की कमी दिखाई जाती है। छात्रों को पढ़ने और शोध कार्यों के लिए आसानी से धन मुहैया कराने की जगह सरकार का ध्यान शिलान्यासों और हरी झंडी दिखाने में लगा रहता है। ऐसे में एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर देना ऐसा फैसला है, जिस पर सिर ही पीटा जा सकता है। मान्यता रद्द करने के पीछे मानकों का पालन न होने को कारण बताया जा रहा है। लेकिन असल मुद्दा यही है कि पिछले काफी वक्त से इस मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को मिले दाखिले पर हिंदू संगठन आपत्ति जता रहे थे और इसके लिए बाकायदा संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन किया जा रहा था। दरअसल इस मेडिकल कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच के 50 छात्रों में से 42 मुस्लिम, एक सिख और केवल 8 हिंदू छात्र जम्मू क्षेत्र से होने की जानकारी सामने आई थी। अधिकतर छात्र कश्मीर से थे। इसी पर हिंदूवादी संगठन हंगामा मचा रहे थे कि जब मेडिकल कॉलेज हिंदुओं के दिए दान से चल रहा है, तो उसमें मुस्लिम छात्रों को दाखिला क्यों दिया जा रहा है। आंदोलनकारी बाकायदा कॉलेज को बंद करने की मांग ही कर रहे थे। जो अब शायद मानकों के बहाने से पूरी कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले पर निराश होते हुए कहा है कि उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की है, यह किसी का उन पर एहसान नहीं है- न मेरा, न यूनिवर्सिटी का। उन्होंने परीक्षा पास करके सीट प्राप्त की है। अब अगर आप उन्हें वहां नहीं पढ़ाना चाहते, तो कहीं और उनका इंतजाम कीजिए। वे किसी के एहसान पर नहीं आए हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीमारी का इलाज करने के बजाय, मरीज को बिना किसी गलती के दंडित किया जा रहा है। अधिक चिंताजनक बात यह है कि यदि एसएमवीडी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ ऐसा किया जा सकता है, तो इसे अन्य जगहों पर भी दोहराया जा सकता है, जिससे मेहनती युवाओं का भविष्य गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। गौरतलब है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने एसएमवीडी से एमबीबीएस कोर्स चलाने की इजाजत वाले आदेश को वापस ले लिया है। इसके बाद से ही छात्र और उनके शिक्षक चिंतित हैं। फैकल्टी सदस्यों ने आरोप लगाया कि हिंदुत्ववादी संगठनों के आंदोलन ने एनएमसी के फैसले को प्रभावित किया है। बता दें कि 2 जनवरी को एनएमसी ने संस्थान का औचक निरीक्षण किया और महज 15 मिनट में फैसला लिया कि 2025-26 सत्र के लिए एमबीबी-एस कोर्स चलाने के लिए दी गई अनुमति वापस ली जाती है। एक बयान में कहा गया है कि यह फैसला अधोसंरचना में गंभीर कमियों के आधार पर लिया गया है। मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर के अनुसार, पिछले दो हफ्तों में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल मटीरियल की कमी और फैकल्टी एवं रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी की कई शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। बोर्ड ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज में शिक्षकों की संख्या करीब 39 प्रतिशत कम थी। ट्यूटर, डेमोंस्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी 65 प्रतिशत कम मिले। मरीजों की संख्या भी निर्धारित मानकों से काफी कम मिली। दोपहर 1 बजे तक ओपीडी में सिर्फ 182 मरीज मौजूद थे, जबकि कम से कम 400 मरीज होने चाहिए थे। अस्पताल में केवल 45 प्रतिशत बेड पर मरीज थे, जबकि मानक 80 प्रतिशत का है। आईसीयू में भी क्षमता से आधे मरीज थे। इसके अलावा कई विभागों में लैबोरेटरी हीं थीं, रिसर्च लैब नहीं थी, लेक्चर थिएटर मानकों के अनुरूप नहीं थे और लाइब्रेरी में सिर्फ 744 किताबें थीं जबकि 1500 किताबें जरूरी हैं। केवल 2 ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे थे जबकि कम से कम 5 थिएटर होने चाहिए थे। पैरा-क्लीनिकल विषयों के लिए उपकरण भी पर्याप्त नहीं थे। मान लिया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक संस्थान में ढेर सारी कमियां थीं, लेकिन उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए या संस्थान ही बंद होना चाहिए।

दूषित पानी से मौतें: जवाबदेही तय करने में नीति क्यों चूकती है?

> नलों से आने वाला पानी दिखने में साफ हो सकता है, लेकिन उसके भीतर घुला जहर आंखों से नहीं दिखता। यही जहर डायरिया, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, किडनी फेलियर और कैंसर जैसी बीमारियों के रूप में सामने आता है।

भारत में पानी को जीवन कहा जाता है लेकिन हकीकत यह है कि आजादी के 78 साल बाद भी यह जीवन हर नागरिक के लिए सुरक्षित नहीं हो पाया है। भारत में स्वच्छ पेयजल को लेकर नीति और अधिकार के बीच की खाई आज भी बनी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए न्यायपालिका स्वच्छ पानी को जीवन का अनिवार्य हिस्सा मान चुकी है लेकिन कार्यपालिका ने अब तक इसे स्पष्ट, लागू करने योग्य और जवाबदेही तय करने वाले कानूनी अधिकार का रूप नहीं दिया है। नतीजा यह है कि सुरक्षित पेयजल सरकारी योजनाओं, बजटीय प्राथमिकताओं और प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर निर्भर एक सुविधा बनकर रह गया है। स्वच्छ पेयजल आज भी भारत में एक गारंटीकृत अधिकार नहीं, बल्कि किस्मत और व्यवस्था की मेहरबानी पर टिकी सुविधा बना हुआ है। हाल ही में मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों ने इस कड़वी सच्चाई को एक बार फिर उजागर कर दिया है। इंदौर की घटना केवल एक शहर या एक राज्य की विफलता नहीं है बल्कि पूरे देश की जल-प्रबंधन व्यवस्था और सरकारी संवेदनहीनता का आईना है। दूषित पानी से लोगों की जान गई, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत की जल नीति में सबसे बड़ी कमी संसाधनों की नहीं, बल्कि नियामक ढांचे, निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही के अभाव की है। यह संकट केवल आपूर्ति का नहीं, बल्कि शासन मॉडल और नीति-निर्माण की गंभीर विफलता का संकेत देता है, जिस पर अब टालमटोल नहीं, ठोस और अधिकार-आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भारत में हर दिन करोड़ों लोग यह जाने बिना पानी पीते हैं कि वह पानी उन्हें जिंदा रखेगा या धीरे-धीरे मौत की ओर ढकेलेगा। ये मौतें अक्सर अखबारों के अंदरूनी पन्नों में सिमट जाती हैं या अस्पताल की रिपोर्ट में "बीमारी से मृत्यु" लिखकर खत्म कर दी जाती हैं जबकि सच यह है कि ये व्यवस्था द्वारा की गई हत्याएं होती हैं। इंदौर, जिसे देश के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है, वहां दूषित पानी से लोगों की मौत होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर 'स्मार्ट सिटी' और 'स्वच्छता मॉडल' का दावा करने वाले शहरों में यह हाल है तो छोटे शहरों और गांवों की स्थिति की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। गंदे नालों का पीने के पानी की पाइपलाइनों से मिल जाना, जर्जर पाइप, जल शुद्धिकरण संयंत्रों की नियमित जांच का अभाव और समय पर क्लोरीनेशन न होना—ये सभी कारण दशकों से जाने-पहचाने हैं। इसके बावजूद हर साल किसी न किसी हिस्से में दूषित पानी लोगों की जान लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार प्रशासन हादसे के बाद हरकत में आता है, उससे पहले नहीं। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की गारंटी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में कह चुका है कि स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा हैं। इसके बावजूद आज तक स्वच्छ पेयजल को एक स्पष्ट, लागू करने योग्य और दंडात्मक मौलिक अधिकार का रूप नहीं दिया गया। सवाल यह है कि जब अदालतें यह मान चुकी हैं, तो सरकारें इसे कानून का ठोस रूप देने से क्यों बचती हैं? क्या इसलिए कि अधिकार बनने के बाद जवाबदेही तय करनी पड़ेगी? सरकारें योजनाएं बनाती हैं—जल जीवन मिशन, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन—लेकिन ये सभी योजनाएं राजनीतिक इच्छाशक्ति और बजट पर निर्भर हैं। योजनाएं बदली जा सकती हैं, स्थगित की जा सकती हैं या कागजों में ही सीमित रह सकती हैं। अगर स्वच्छ पानी अधिकार बन जाए, तो सरकार को हर नागरिक तक सुरक्षित पानी पहुंचाने के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह होना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि आज भी पानी को अधिकार नहीं, बल्कि "सरकारी सुविधा" के रूप में पेश किया जाता है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा गरीब, दलित, आदिवासी और हाशिए के समाज को भुगतना पड़ता है। शहरों में संपन्न वर्ग बोतलबंद पानी खरीद लेता है, आरओ लगवा लेता है लेकिन झुग्गियों और गरीब बस्तियों में लोग वही पानी पीने को मजबूर होते हैं जो नल या हैंडपंप से आता है—चाहे वह दूषित हो या नहीं। ग्रामीण भारत में आज भी महिलाएं मीलों पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर हैं, और वह पानी भी अक्सर सुरक्षित नहीं होता। यह स्थिति बताती है कि राज्य धीरे-धीरे अपनी जिम्मेदारी नागरिकों पर थोप चुका है। राजनीति में पानी अक्सर केवल चुनावी वादों तक सीमित रह जाता है। सड़क, बिजली, गैस और इंटरनेट पर तो बहस होती है लेकिन पानी जैसे बुनियादी सवाल को गंभीरता से नहीं उठाया जाता। जब तक किसी इलाके में मौतें नहीं होतीं या मीडिया का दबाव नहीं बनता, तब तक प्रशासन नींद में रहता है। इंदौर की घटना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है—पहले मौतें, फिर जांच समिति, फिर आश्वासन, और कुछ समय बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि समाज ने भी दूषित पानी को अपनी नियति मान लिया है। "थोड़ा बहुत गंदा पानी तो चलता है" जैसी सोच ने इस संकट को और गहरा किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी जहर 'थोड़ा' हो सकता है? क्या राज्य की लापरवाही से किसी की मौत होना सामान्य बात हो सकती है?

● बाबूलाल नागा

ऐसे में केवल जीडीपी ...

राजेश जैन

चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के शोर में छूट न जाए असली सवाल

> सरकार इस उपलब्धि को अपनी नीतियों की सफलता के रूप में पेश कर रही है। उसके मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में आई तेजी ने विकास को रफ्तार दी है। बेहतर बुनियादी ढांचा, बढ़ता सरकारी पूंजीगत खर्च और मांग में सुधार को भी इस उछाल की बड़ी वजह बताया जा रहा है। यह बाजार के विस्तार, उत्पादन क्षमता, सेवा क्षेत्र की मजबूती और निवेश के भरोसे का संकेत जरूर है लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि जीडीपी का बढ़ना अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं देता कि हर नागरिक की आमदनी या जीवन स्तर भी उसी अनुपात में बढ़े।

देश के आर्थिक सफर में साल 2025 एक अहम पड़ाव बनकर दर्ज हो गया है। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना निस्संदेह गर्व का विषय है। यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं बल्कि बीते दशकों में बने आर्थिक ढांचे, नीतिगत फैसलों, उद्यमिता और आम भारतीय की मेहनत का नतीजा है लेकिन हर बड़ी सफलता अपने साथ कुछ असहज सवाल भी लेकर आती है। सवाल यह नहीं कि भारत चौथे नंबर पर पहुंचा या नहीं बल्कि यह है कि क्या यह तरक्की जमीन पर भी महसूस हो रही है? क्या बढ़ती जीडीपी के साथ रोजगार की गुणवत्ता, शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बेहतर हो रही है? अगर हां, तो यह विकास टिकाऊ है। अगर नहीं तो जश्न के बीच यह चेतावनी की घंटी है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत का पैमाना माना जाता है। यह बताता है कि एक तय समय में देश के भीतर कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ। इसमें देश की सीमाओं के भीतर काम कर रही विदेशी कंपनियों का योगदान भी शामिल होता है। भारत के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब यह है कि अब देश की जीडीपी का

कुल आकार करीब 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और वह जापान से आगे निकल चुका है। अब अमेरिका (30.6 ट्रिलियन डॉलर), चीन (19.4 ट्रिलियन डॉलर) और जर्मनी (5 ट्रिलियन डॉलर) ही हमसे आगे हैं। ताजा एडवांस अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो पहले के अनुमानों से ज्यादा है। नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच महज 0.6 प्रतिशत का अंतर यह संकेत देता है कि महंगाई फिलहाल काबू में है। सरकार के लिए यह तर्क भी अहम है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है। 2047 तक उच्च मध्यम-आय वाला देश बनने का लक्ष्य अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक ठोस रोडमैप के तौर पर पेश किया जा रहा है। विपक्ष की नजर में तस्वीर इतनी उजली नहीं है। उसका सवाल सीधा है-अगर अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो आम आदमी की जिंदगी आसान क्यों नहीं हो रही? विपक्ष का तर्क है कि विकास का फायदा कुछ बड़े कॉर्पोरेट समूहों तक सीमित है। प्रति व्यक्ति आय में असमानता बनी हुई है, ग्रामीण इलाकों की आमदनी धीमी रफ्तार से बढ़ रही है और युवाओं के लिए स्थायी व सम्मानजनक रोजगार अब भी बड़ी चुनौती है। छोटे उद्योग, किसान और असंगठित क्षेत्र अभी भी दबाव में हैं। विपक्ष यह भी याद दिलाता है कि भारत की बड़ी आबादी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करती है, जहां न तो सामाजिक सुरक्षा है और न ही आय की स्थिरता। ऐसे में केवल जीडीपी रैंकिंग को विकास का अंतिम पैमाना मानना भ्रामक हो सकता है। भारत में पानी को जीवन कहा जाता है लेकिन हकीकत यह है कि आजादी के 78 साल बाद भी यह जीवन हर नागरिक के लिए सुरक्षित नहीं हो पाया है। भारत में स्वच्छ पेयजल को लेकर नीति और अधिकार के बीच की खाई आज भी बनी हुई है।

कविता पोस्टर ...

विवेक रंजन श्रीवास्तव

किताबों का मूल्य अमूल्य

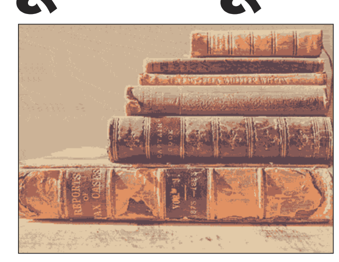

पुराना समय स्कूलों में हस्त लिखित व सायक्लोस्टाइल पत्रिकाओं का जमाना था। हमने वह जमाना भी जिया है जब रचना करते थे , सुंदर हस्तलेख में लिखते थे , एक पता लिखा टिकिट लगा लिफाफा साथ रखते थे कि यदि संपादक जी को रचना पसंद न आई तो संपादक के अभिवादन व खेद सहित रचना वापस मिल जायेगी , कहीं और छपने के लिये भेजने को फिर डाक निकलने के समय से पहले चिट्ठी लाल डिब्बे में डालने जाते थे . रचना छपने से पहले उसकी स्वीकृति आ जाती थी . बुक स्टाल पर जाकर पत्रिका के नये अंक उलटते पलटते थे, इस जिज्ञासा में कि रचना छपी ? फिर पारिश्रमिक का चैक या मनीआर्डर जिसे अपेक्षा से बहुत कम होने के चलते कई पत्रिकायें पत्रं पुष्प लिखती थी आता था . कितना मजा आता था . यह सारी प्रक्रिया अनवरत जीवनचर्या बन गई थी . इसे हम मित्रमण्डली में लेखनसुख कहते थे . जब कोई खूब छप चुकता था , तब उसकी किताब छपने की बारी आती थी रायल्टी के एग्रीमेंट के साथ प्रकाशक के आग्रह पर किताबें छपती थीं . ईमेल ने और आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम ने आज के लेखको को इस सुख से वंचित कर दिया है सिद्धांत है कि ढ़ेर सा पढ़ो , खूब सा गुनो , तब थोड़ा सा लिखो . जब ऐसा लेखन होता है तो वह शाश्वत बनता है पर आज लिखने की जल्दी ज्यादा है , छपने की उससे भी ज्यादा . हर डायरी अब पुस्तक बन रही है। आज सम्पादक की कसौटी से अपनी रचना गुजारना पसंद न हो तो ब्लाग , फेसबुक पोस्ट जैसे संसाधन है . सीधे कम्प्यूटर पर लिखो और एक क्लिक करते ही दुनियां भर में छप जाओ . रचना की केवल प्रशंसा ही सुननी हो और आपकी भक्त मण्डली बढ़िया हो तो व्हाट्सअप ग्रुप बना लो , आत्ममुग्ध रहो इस सारे आधुनिकीकरण ने डाटा बेस में भले ही हिन्दी किताबो की संख्या और पत्रिकाओ का सर्क्युलेशन बढ़ा दिया हो पर वास्तविक पाठक कही खो गया है . लोग ठकुरसुहाती करते लगते हैं . एक दिन मेरी एक कविता अखबार के साप्ताहिक परिशिष्ट में छपी , मेरे एक मित्र मिले और उन्होने उसका उल्लेख करते हुये मुझे बधाई दी , मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज भी अच्छी रचनाओ के पाठक मौजूद हैं पर जैसे ही मैने उनसे रचना के कथ्य पर चर्चा की, मुझे समझ आ गया कि उन्होने मेरे नाम के सिवाय रचना मे कुछ नही पढ़ा था और वे मुझे बधाई भी इस बहाने केवल इसलिये दे रहे थे क्योकि मेरे सरकारी ओहदे के कारण उनकी कोई फाइल मेरे पास आई हुई थी . पाठको की इसी गुमशुदगी के चलते नये नये प्रयोग चल रहे हैं . कविता पोस्टर बनाकर प्रदर्शनी लगाई जा रही हैं . काव्य पटल बनाकर चौराहो पर लोकार्पित किये जा रहे हैं . किसी भी तरह पाठक को साहित्य तक खींचकर लाने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं . इन्ही प्रयासो में से एक है ₹पुस्तक मेला₹ जहाँ लेखको , पाठको और प्रकाशको का जमघट लगता है . सरकारी अनुदान से स्कूल कालेज के पुस्तकालयो के लिये किताबें खरीदी जाती हैं जिनसे आंकड़े कुछ प्रदर्शन योग्य हो जाते हैं .

जरा हटके

दूसरी जो सबसे ...

गौतम चौधरी

यह तो वक्त ही बताएगा कि पेसा कानून से झारखंड के आदिवासियों को फायदा हुआ या हानि

अंततोगत्वा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने झारखंड में पेसा कानून लागू कर दिया। लागू कानून में कई विसंगतियां हो सकती है लेकिन इस कानून को अमली जामा पहनाने के लिए निःसंदेह हेमंत और उनकी सरकार धन्यवाद के पात्र हैं। हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस पेसा को मान्यता दी है, उस पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वर्तमान पेसा अधिसूचना की यदि खामियों पर प्रकाश डालें तो उसमें चार बड़ी विसंगतियां देखने को मिलती है। पहली विसंगति तो यह बताया जा रहा है कि पेसा नियमावली आदिवासी हितों की रक्षा के लिए बना था। इसमें शिड्यूल्ड एरिया चिंहित करने की बात कही गयी थी। इसका चिंहिंकरण पारंपरिक आधार पर करना था और जहां पारंपरिक आधार काम नहीं कर रहा है वहां ग्राम सभा की समिति को करना था लेकिन सरकार ने नियमावली बनाते समय उसकी मूल भावना को ही खत्म कर दिया.है। अब शिड्यूल्ड एरिया उपायुक्त के द्वारा बनायी गयी समिति तय करेगी। हालांकि पेसा कानून की अधिसूचना में इस बात का साफ-साफ जिक्र नहीं किया गया है लेकिन यह जरूर बताया गया है कि आदिवासियों के गांवों का सीमांकन उपायुक्त के द्वारा बनायी गयी समिति करेगी। इसके कारण आने वाले समय में आदिवासियों के साथ बड़ी समस्या होने वाली है। दूसरी जो सबसे बड़ी खामी बतायी जा रही है, पेसा नियमावली के पहले पन्ने से ही रूढ़ि-प्रथा को हटा दिया गया है। अब जब रूढ़ि-प्रथा ही नहीं है तो आदिवासियों की मूल पहचान ही खत्म हो जा रही है। पेसा तो रूढि और प्रथाओं को अंगीकार करने वालों के लिए लाया गया था। जो अपनी प्रथाओं को छोड़ चुके हैं और आस्था बदल लिए हैं उनके लिए तो अलग से कानून है ही लेकिन पेसा तो आदिवासियों की परंपरा और रूढ़ियों की रक्षा के लिए ही लया गया था। तीसरा आरोप यह है कि सरकार ने ग्राम सभा को सशक्त बनाने के बजाय उसे कमजोर करने का काम किया है। मसलन, पहले सीएनटी से जुड़े मामलों में ग्राम सभा की निर्णायक भूमिका होती थी लेकिन अब यह अधिकार उपायुक्त (डीसी) को सौंप दिया गया है। इससे तो झारखंड के आदिवासियों को पहले से प्राप्त संरक्षक तीन कानून, जैसे - सीएनटी, एसपीटी और विल्किंसन रूल भी कमजोर हो जा रहा है। इस तीन के अलावे चौथी विसंगति यह बतायी जा रही है, वर्तमान पेसा अधिसूचना में ग्राम सभा के द्वारा यदि किसी बात पर निर्णय में विलंब हो रही है तो एक निश्चित समय सीमा के बाद उस निर्णय को स्वतः पास माना जाएगा। यह ग्राम सभा को कमजोर करने वाला कानून है। इस नियम ने प्रशासन और स्थानीय नौकरशाहों को ग्राम सभा से ज्यादा ताकत प्रदान कर दिया है, जबकि मूल पेसा कानून में ग्राम सभा का निर्णय ही सर्वोपरी माना गया है। इस प्रकार कई मामलों में पेसा को उचित और मजबूत बताया जा रहा है लेकिन पेसा से झारखंड के आदिवासियों को बहुत फायदा तो होता नहीं दिख रहा है।

हर दिन उत्साह

हमारे जीवन में हर दिन उत्साह रहें । यह एक ऐसी सकारात्मक उर्जा हैं जो हमारे जीवन में प्रेरणा और उमंग भर देती है । वह लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक व संग होती है । उत्साह ऐसा अद्भुत गुण है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें मैदान नहीं छोड़ने देता हैं । वह आशावान बनाए रखता है । उत्साह शोर नहीं मचाता हैं पर यह ऑखों में दिखता है। यह चाल में झलकता हैं । वह शब्दों में उभरता है । हमारे भीतर जब उद्देश्य की लौ जलती है तो उत्साह की अग्नि उसे हवा देती है। वह बाधाएँ मानो कहीं खो जाती हैं। 9 जनवरी का इतिहास भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Diwas) मनाया जाता है जो भारत के विकास में भारतीय समुदाय के द्वारा विश्व में योगदान को सम्मान देने के लिए है । वह इसी की याद में 2003 से हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas) मनाया जाता है । वह आज के दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिसके कारण यह दिन महत्वपूर्ण है । वह साथ ही, 1811 में पहला महिला गोल्फ टूर्नामेंट, 1927 में सुंदरलाल बहुगुणा (चिपको आंदोलन) का जन्म और 2007 में स्टीव जॉब्स द्वारा iPhone लॉन्च जैसी घटनाएँ भी इसी दिन हुईं। 9 जनवरी 1982 को भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान दल अंटार्कटिका पहुंचा था । आज कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों के साथ-साथ ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व का भी दिन हैं । वह साथ ही आज के दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं और मशहूर हस्तियों के जन्मदिन आदि भी दर्ज हैं। हम इस तरह जीवन में आगे बढ़ते ही जायें । हमसे उत्साह परफैक्ट होने की माँग नहीं करता हैं किन्तु वह काम के प्रति पूरी लगन जरूर चाहता हैं । वह तब काम स्वयंमेव ही सफल हो जाता हैं। ध्यान रखने लायक बात है कि टालमटोल व तुलना करना उत्साह के शत्रु को खुला न्यौता देना हैं । असली उद्यमी इन सब बाधाओं को टालकर ही हर दिन उत्साह से आगे बढ़ता ही जाता हैं । अतः हम जीवन के हर दिन उत्साह बनायें रखें । यही हमारे लिए काम्य हैं ।

> ओम अर्हम सा !

> प्रदीप छाजेड़

आजम खान रामपुर जेल में जमीन पर सो रहे

पत्नी ने की मुलाकात, बोलीं- साहब को सर्दी-बुखार, बेड तक नहीं दिया

मुलाकात

तमसा संकेत, एजेंसी

रामपुर। यूपी में रामपुर जिला जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से पत्नी तंजीन फातिमा मिलने पहुंचीं। मुलाकात के बाद बाहर आते ही उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा- आजम साहब को कई दिनों से सर्दी-जुकाम और बुखार है। इसके बावजूद उन्हें बेड तक नहीं दिया गया। कड़ाके की ठंड के बीच वह जमीन पर सोने को मजबूर हैं। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद तंजीन ने कहा- उम्र और सेहत को देखते हुए आजम को नियमों के तहत 'ए-श्रेणी' की सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन, जेल प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है। कई बार अधिकारियों के सामने यह मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन हर बार अनदेखी की गई। यह मानवीय नहीं है। इससे पहले भी आजम से मुलाकात के बाद तंजीन और बड़े बेटे अदीब ने जेल में ठंड से बचाव के इंतजामों को लेकर सवाल उठाए थे। आजम खान 2017 में अखिलेश सरकार में नगर विकास मंत्री थे। विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार सीट से बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़ाना चाहते थे। लेकिन, अब्दुल्ला की उम्र में छोटे थे। एजुकेशन सर्टिफिकेट में दर्ज उनकी डेट ऑफ बर्थ आड़े आ रही थी।

> जेल अधीक्षक राजेश यादव ने आरोपों को निराधार बताया। कहा- आजम खान की तबीयत सामान्य है। उन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं है। प्रशासन के मुताबिक, जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम नियमित रूप से मेडिकल जांच कर रही है। जेल मैनुअल के अनुसार जो भी सुविधाएं तय हैं, दी जा रही हैं। आरोप तथ्यहीन हैं।

23 जनवरी को शत्रु संपत्ति मामलों की सुनवाई

इधर, आज से जुड़े शत्रु संपत्ति के दो मामलों की एक साथ सुनवाई को लेकर अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई 23 जनवरी को होनी है। ये मुकदमे 2019 में अजीमनगर थाने में दर्ज हुए थे, जिनमें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी शत्रु संपत्ति का आरोप है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में दर्ज उनकी डेट ऑफ बर्थ आड़े आ रही थी।

अन्य मामलों में भी बढ़ सकती हैं मुश्किलें

इसके अलावा क्वालिटी बार कब्जा मामले में भी सुनवाई जारी है। गुरुवार को इस केस में गवाह गगन अरोड़ा अदालत में पेश हुए थे। आने वाले दिनों में इन मामलों की सुनवाई आजम की कानूनी और राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना सकती हैं।

कैदियों को कब मिलती हैं खास सुविधाएं

यूपी के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने बताया कि जेल में सभी कैदियों को एक समान सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि, अगर सरकार किसी कैदी को 'सुपीरियर कैदी' का दर्जा देती है तो फिर उसकी सुविधाएं बढ़ सकती हैं। उसे बेड या जरूरत का अन्य सामान दिया जा सकता है। इसके अलावा, कोर्ट के समक्ष भी कैदी अपनी जरूरत की चीजें मांग सकता है। अगर कोर्ट अनुमति देती है तो फिर जेल प्रशासन उसकी व्यवस्था करवाता है।

एआई और रोबोटिक्स पर विंटर स्कूल का आयोजन

छात्रों ने जेनरेटिव एआई व ड्रोन तकनीक में लिया प्रशिक्षण

तमसा संकेत, संवाददाता

साहिबाबाद। औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 स्थित इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स जैसे अत्याधुनिक और भविष्य-उन्मुख विषयों पर आधारित एक सप्ताह का "विंटर स्कूल–2026" का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना, उनकी नवाचारी सोच को विकसित करना तथा व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना रहा। इस विंटर स्कूल में चौधरी छबील दास पब्लिक स्कूल (सीसीडीपीएस), गाजियाबाद के 31 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रतिदिन दो सत्रों में आयोजित किया गया। प्रथम सत्र में प्रो. (डॉ.) तनवीर इकराम ने जेनरेटिव एआई की मूल अवधारणाओं, इसके औद्योगिक अनुप्रयोगों तथा एआई आधारित प्रोजेक्ट्स पर विद्यार्थियों को हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम के समन्वयक एवं यांत्रिक अभियांत्रिकी विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) एस. पी. सिंह ने बताया कि विंटर स्कूल का पाठ्यक्रम वर्तमान औद्योगिक आवश्यकताओं एवं उभरती तकनीकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। संस्थान के निदेशक प्रो. (डॉ.) ए. के. सोलंकी ने कहा कि एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन भविष्य की प्रमुख तकनीकें हैं, जिनमें दक्षता विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला बनेगी।

फास्ट न्यूज

कानपुर गैंगरेप में आरोपी दरोगा, इसलिए हल्की धाराएं लगाई

कानपुर। कानपुर गैंगरेप केस में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट भी नाराज हुआ। 5 जनवरी की रात को गैंगरेप होने के बाद 8 जनवरी को पीड़िता को कोर्ट लाया गया। यहां पहले तो 3 घंटे तक पुलिस जांच अधिकारी नहीं पहुंचे। पीड़िता रूम के बाहर बैठी रही। मामले की शुरुआत 5 जनवरी की रात 10 बजे हुई। 14 साल की पीड़िता घर से निकली थी।

6 किमी की रफ्तार से चल रही हवा

वाराणसी। वाराणसी में आज भले ही कोहरा कम गिर रहा, लेकिन 6 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही ठंड हवाओं से गलन बढ़ गई है। अधिकतम 18 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया दो दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों से ठंडी और शुष्क पछुआ हवा उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, जिससे दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

रायबरेली में मृत मिली गैंगेटिक डॉल्फिन

कानपुर। रायबरेली जिले के राही ब्लॉक स्थित कसहेटी गांव की नहर में एक दुर्लभ गैंगेटिक डॉल्फिन का शव मिला है। कानपुर के बाद रायबरेली में डॉल्फिन की मौत का यह मामला वन्यजीव प्रेमियों और वन विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है। प्रारंभिक जांच और कानपुर में हुए पोस्टमार्टम के बाद डॉल्फिन की मौत का मुख्य कारण 'हार्ट फेलियर' सामने आया है।

राम मंदिर क्षेत्र के होटल- होम स्टे को चेतावनी, पकड़े जाने पर लायसेंस निरस्त होगा

नॉनवेज की डिलीवरी पर रोक

तमसा संकेत, एजेंसी

अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आस पास नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये आदेश ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू किया गया है। इस संबंध में होटल, होम स्टे और ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों को अवगत करा दिया गया है। उन्हें चेतावनी दी गई है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही गई है। इस आदेश के आने के बाद से फिर से बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इस आदेश के पक्ष में तो कुछ लोग विरोध में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं, ये तय करने का अधिकार किसी और को नहीं, सिर्फ उन्हें है। वहीं कई लोग इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। अयोध्या में नॉनवेज खाने और बेचने पर रोक कोई नई व्यवस्था नहीं है। अमावां राम मंदिर के पूर्व सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल की पुस्तक 'अयोध्या रीविजिटेड' में इसका उल्लेख मिलता है।

9 जनवरी से आदेश लागू

9 जनवरी को होटल, गेस्ट हॉउस, होम स्टे और ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों को आदेश से अवगत करा दिया गया है। नियम तोड़ने पर होटल मालिक और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

नॉनवेज डिलीवरी की मिली थी शिकायत

सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया- राम मंदिर और इसके आस पास नॉनवेज की बिक्री पर पहले से रोक है। लेकिन कुछ होटल, गेस्ट हॉउस और होम स्टे वाले इसका पालन नहीं कर रहे हैं। शिकायत मिली थी कि यहां पर आने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन नॉनवेज मंगाकर परोसा जा रहा है। इसलिए अब राम मंदिर और इसके आस पास के क्षेत्र में नॉनवेज की ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है।

> *शिकायत मिली थी कि यहां पर आने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन नॉनवेज मंगाकर परोसा जा रहा है। इसलिए अब राम मंदिर और इसके आस पास के क्षेत्र में नॉनवेज की ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।*

एमआईईटी और अनुदीप फाउंडेशन के बीच एमओयू

एकेडमिक- इंडस्ट्री अंतर पाटने की दिशा में बड़ा कदम

तमसा संकेत, संवाददाता

मेरठ। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एमआईईटी) ने उद्योग-संरेखित शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अनुदीप फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। अनुदीप फाउंडेशन एक प्रतिष्ठित डीप-टेक स्किलिंग एवं आजीविका संवर्धन संस्था है, जो युवाओं को उद्योग-तैयार बनाने के लिए कार्यरत है। यह एमओयू एमआईईटी के कैंपस डायरेक्टर प्रो. डॉ. संजय कुमार सिंह तथा अनुदीप फाउंडेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अजय कुमार सिंह द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया। सहयोग का उद्देश्य अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटते हुए छात्रों के लिए इंटर्नशिप, उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुख अवसरों के संरचित मार्ग विकसित करना है। इस साझेदारी के तहत एमआईईटी के विद्यार्थियों को समकालीन तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव, हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा वर्तमान उद्योग मांगों के अनुरूप प्लेसमेंट-उन्मुख कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। एमओयू हस्ताक्षर समारोह एमआईईटी के चेयरमैन विष्णु शरण एवं वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल के दूरदर्शी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अनुदीप फाउंडेशन की ओर से रोहित त्रिपाठी और निर्वेश कुमार उपस्थित रहे, जबकि एमआईईटी से प्रो. डॉ. नरेश कुमार (डीन—सीएसई एवं आईटी), श्री रोहित अग्रवाल (एसोसिएट डीन), डॉ. विकास श्रीवास्तव (विभागाध्यक्ष—सीएसई), डॉ. स्वाति शर्मा (विभागाध्यक्ष—आईटी) तथा डॉ. रामबीर सिंह (विभागाध्यक्ष—सीएसई एआई/एआईएमएल) शामिल रहे।

धान क्रय केंद्र पर किसानों का प्रदर्शन दसवें दिन में प्रवेश

तमसा संकेत, संवाददाता

सूरतगंज (बाराबंकी)। ब्लॉक स्थित सरकारी धान क्रय केंद्र बरैय्या पर किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। धान रिजेक्ट किए जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को केंद्र परिसर में विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन गुरुवार को हुए हंगामे के बाद आरोप-प्रत्यारोप के बीच 10वें दिन में प्रदर्शन प्रवेश कर गया है। धरने का नेतृत्व भाकियू टिकैत गुट के तहसील अध्यक्ष शारदा बख्श सिंह कर रहे हैं। उनके साथ सूरतगंज ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, मंडल अध्यक्ष समीर यादव उर्फ संदीप और जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद भी मौजूद रहे। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसानों के जुटने से केंद्र पर धान खरीद का कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। जानकारों की माने तो यह धरना प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा जबकि कई बार किसानों के बीच समझौता भी हो चुका है। किसानों और संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि धान तौल और गुणवत्ता जांच के दौरान केंद्र पर तैनात एसएमआई और उनके पल्लेदारों ने गुरुवार को किसानों से अभद्रता और दुर्व्यवहार किया। जब किसानों ने इसका विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट करने का प्रयास भी किया गया। भाकियू टिकैत गुट के नेताओं ने कहा कि सरकारी धान क्रय केंद्र किसानों की सुविधा और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यहां किसानों का शोषण हो रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक किसी उच्चाधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की जाती और दोषी एसएमआई के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सूचना मिलने पर रामनगर के नायब तहसीलदार अभिनव सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत करने का प्रयास किया। हालांकि, किसान उच्चाधिकारी के आने की मांग पर अड़े रहे। धरना प्रदर्शन में ब्लॉक महामंत्री प्रवेश कुमार, ब्लॉक मीडिया प्रभारी त्रिभवन चौहान, राजेंद्र वर्मा, नौमी लाल, पुष्पेंद्र, हरदेव, कल्लू यादव, दिनेश, राम बरन, नकछेद, बालक राम, हरिश्चंद्र, विशाल शुक्ला, हरिहर वर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

युवक का शव कब्र खोदकर निकाला गया

कानपुर में परिजनों ने तीसरे दिन हत्या का शक जताया, पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

■ गंगा किनारे दफनाए गए शव को पुलिस की मौजूदगी में खोदकर निकाला गया।

तमसा संकेत, एजेंसी

नरवल। कानपुर के बिधनू स्थित कडरी चंपतपुर गांव में 22 वर्षीय युवक श्रीचंद की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसी दिन परिजनों ने शव दफनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। तीसरे दिन परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए पुलिस से शिकायत की। फिर शुक्रवार दोपहर में कब्र खोदकर दफनाए गए शव को बाहर निकाला गया। परिजनों की मांग पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने यह कार्रवाई की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है, ताकि मौत के सही कारणों का खुलासा हो सके। गुरुवार को परिजनों द्वारा बिधनू पुलिस को शिकायत पत्र दिए जाने के बाद शुक्रवार को बिधनू और महाराजपुर पुलिस, एसीपी घाटमपुर तथा फोरेंसिक टीम नजफगढ़ गंगा घाट पहुंची। करीब पौने सात बजे ग्रामीणों ने सूचना दी कि वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे मृत पड़ा है। टीम ने परिजनों की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवाकर पंचनामा किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। मौके से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए गए।

घर से निकलने के बाद मिली थी मौत की सूचना

मृतक के पिता योगेश चंद्र के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 6 बजे श्रीचंद घर से निकला था। करीब पौने सात बजे ग्रामीणों ने सूचना दी कि वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे मृत पड़ा है। परिजन उसे बिधनू स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अंतिम संस्कार के बाद जताई गई हत्या की आशंका

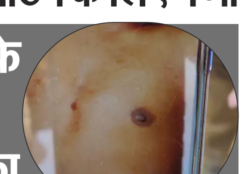

मृतक श्रीचंद पुत्र योगेश चंद्र की मंगलवार को संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। परिजनों ने बुधवार को महाराजपुर थाना क्षेत्र के नजफगढ़ गंगा घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। हालांकि, अंतिम संस्कार के दौरान सीने पर चोट के निशान दिखने के बाद परिजनों को हत्या की आशंका हुई, जिसके चलते पुलिस से पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की गई।

> घाटमपुर एसीपी कृष्ण कांत ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर गंगा घाट से शव को बाहर निकलवाया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कार्यवाई : वाराणसी में 2 घंटे तलाशी ली, कोडीन कफ सिरप कांड में दर्ज है मुकदमा

शुभम जायसवाल के करीबी प्रशांत के घर पुलिस का छापा

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी। कोडीन कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के करीबी और राधिका इंटरप्राइजेज और राजेंद्र ड्रैग एजेंसी के मालिक प्रशांत उपाध्याय के घर वाराणसी पुलिस ने छापेमारी की। देर रत मंडुआडीह थाना क्षेत्र के मड़ौली स्थित प्रशांत के घर पर एसीपी क्राइम के नेतृत्व में रामनगर, आदमपुर और कोतवाली पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज वहां से जब्त कर अपने साथ ले गई। कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में शुभम के साथ दर्ज नाम में प्रशांत का भी नाम है। प्रशांत सप्तसागर दवा मंडी में बड़े कफ सिरप व्यापारी के रूप में जाना जाता है। पुलिस को अनुमान है कि उसकी फर्म द्वारा करोड़ों के कोडीन कफ सिरप का लेनदेन किया है।

घर पर नहीं मिला प्रशांत

छापेमारी के दौरान प्रशांत घर पर नहीं मिला। पुलिस सूत्रों के अनुसार मौके से पुलिस ने कई फर्जी दस्तावेज, कोडीन कफ सिरप के रैपर, शीशियां और पेन ड्राइव और लैपटॉप को जब्त किया है। एसीपी ने बताया - प्रशांत की दो फर्म राधिका इंटरप्राइजेज और राजेंद्र ड्रग एजेंसी का शैली ट्रेडर्स से क्या लेनदेन था।

■ वाराणसी के मंडौली इलाके में प्रशांत उपाध्याय के घर पुलिस ने की छापेमारी

पुलिस ने देर रात की छापेमारी

वाराणसी की कोतवाली, आदमपुर और रामनगर पुलिस ने बीती रात एसीपी विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में कोडीन कफ सिरप कांड में कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 235/2025 के अंतर्गत आरोपी प्रशांत उपाध्याय के घर पहुंची। एसीपी ने बताया - मुकदमे के संबंध में हमने प्रशांत के मकान पर छापेमारी की है और कई अहम् दस्तावेज मिले हैं।

सिरप का बड़ा कारोबारी है प्रशांत उपाध्याय

कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में शुभम के साथ दर्ज नाम में प्रशांत का भी नाम है। प्रशांत सप्तसागर दवा मंडी में बड़े कफ सिरप व्यापारी के रूप में जाना जाता है।

माघ मेले में काला चश्मा पहनकर निकले सतुआ बाबा

इटली की लुक्रेशिया ने हिंदू धर्म अपनाया, मंत्र सीख रहीं

तमसा संकेत, एजेंसी

प्रयागराज। प्रयागराज माघ मेले का आज 7वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बावजूद करीब 10 लाख श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे। साधु-संत, अखाड़े और कल्पवासी संगम की रेती पर डेरा जमाए हैं। शुक्रवार को सतुआ बाबा ने 100 संतों के साथ माघ मेला इलाके में शोभा यात्रा निकाली। वह काला चश्मा पहनकर चल रहे थे। साधु-संत हाथ में तलवार और त्रिशूल लिए थे। सीएम योगी भी शनिवार को माघ मेला पहुंच रहे हैं। वे सतुआ बाबा के आश्रम जाएंगे। साधुओं के साथ भोजन करेंगे। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान पर्वों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। विदेशी श्रद्धालु भी संगम पहुंच रहे। 22 साल की लुक्रेशिया इटली से यहां आई हैं। वो दिन-भर भजन-कीर्तन करती हैं। भारतीय संस्कृति में रमी लुक्रेशिया कहती हैं- महाकुंभ ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं सनातन (हिंदू) धर्म अपना चुकी हूं। मंत्रोच्चार सीख रही हूं। महाकुंभ में 'दातून बॉय' नाम से मशहूर हुए आकाश माघ मेले में भी थार से दातून बेचने आए हैं। उनके साथ 40-50 लड़कों की टीम है, जो जगह-जगह कैंप लगाकर दातून बेच रही। सभी ने आकाश और मलाइका अरोड़ा की तस्वीर छपी टी-शर्ट पहन रखी है। आकाश ने कहा- भारतीय महिलाओं और बहन-बेटियों को मुफ्त में दातून बांट रहा हूं। जबकि विदेशियों को 1,000 रुपए में दातून दे रहा हूं। भारत को अंग्रेजों ने लूटा था, इसलिए मैं उन्हें फ्री में दातून नहीं दूंगा। सीएम योगी कल माघ मेला आयेंगे। ऐसे में परेड ग्राउंड की पार्किंग को खाली कराया जा रहा है। सड़क किनारे लगी दुकानों को हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा में सतुआ बाबा चश्मा लगाकर चल रहे हैं। उनके साथ अन्य साधु-संत भी चल रहे हैं। कुछ संत पैदल, कुछ ट्रैक्टर पर तो कुछ घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं। डमरू बजाते और बैंड बाजा की धुनों पर मस्त मलंग होकर साधु-संत आगे बढ़ रहे हैं।

'जी राम जी' अधिनियम का विरोध करने वालों को राम नाम से नफरत करने वाला बताया

केशव मौर्य ने सपा और विपक्ष पर साधा निशाना

विवाद

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में सपा को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (जी राम जी) का विरोध करने वालों को राम नाम से नफरत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को आगरा दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने प्रेसवार्ता के दौरान 'जी राम जी' अधिनियम 2025 से ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही इस अधिनियम का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा-'जी राम जी' विकसित भारत का रोडमैप है। जब

आगरा में एयरपोर्ट से बाहर निकलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।

तक विकसित गांव नहीं होंगे तब तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का सपना अधूरा रह जाएगा। इस अधिनियम में राम नाम शब्द आने से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव जब से बिहार में चुनाव हारकर आए हैं, तब से वे बौखलाए हुए हैं...घबराए हुए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि 2027 में सरकार बना लेंगे...समाज को बांटकर राज कर लेंगे। झूठ फैलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीट पा लिए थे, उस भ्रम को हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, बिहार की जनता ने नकार दिया। देश मोदी जी के साथ है, देश मोदी के साथ था, देश भाजपा के साथ है।

> **"डिप्टी सीएम ने कहा- महात्मा गांधी का हम सब आदर करते हैं। कांग्रेस हो...सपा हो...टीएमसी हो...डीएमके हो...आरजेडी हो, इन सबको राम नाम से नफरत है। इसका क्या कारण है, वही जाने। जी राम जी में स्पेलिंग नाम के क्रम में राम नाम शब्द आ गया है, इसलिए वो मनरेगा के इस नये अधिनियम से नफरत कर रहे हैं।**

ममता बनर्जी पर बोला हमला

पश्चिम बंगाल में जांच एजेंसी का विरोध करने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा-पश्चिम बंगाल में टीएमसी जा रही है, इसलिए बौखलाई हुई है। भाजपा आ रही है। इससे टीएमसी घबराई हुई है। यदि कोई जांच एजेंसी जांच करनी जाती है तो किसी मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता है कि वह जांच में कोई हस्तक्षेप करे। ममता बनर्जी ने जांच में हस्तक्षेप करके ये साबित कर दिया है कि वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है।

समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा है

हाल ही में सपा ने भाजपा के ब्रह्मण विधायकों को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है। इस सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा-समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा है। उनके विधायक भाजपा में आना चाहते हैं, हम लोग लेना नहीं चाहते।

विनय कटियार ने हाल ही में एक बयान दिया कि वे अयोध्या से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा-मैं उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता।

डिप्टी सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

पीडीए की ये बताई फुल फॉर्म

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा-पीडीए...परिवार डवलपमेंट एजेंसी है, इनकी हवा निकल चुकी है। ये पीडीए लेकर बिहार चुनाव में गए थे, इनका कोई प्रत्याशी नहीं था। अखिलेश यादव वहां पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह से पहुंच गए। अखिलेश का कुछ पता नहीं है, आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे। उनका काम है।

नजीबाबाद फ्लाईओवर ब्रिज की मरम्मत पर विवाद

अधिकार क्षेत्र को लेकर यूपी सेतु निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग में बहस

तमसा संकेत, संवाददाता

बिजनौर / नजीबाबाद। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने रेलवे क्रॉसिंग पर बने फ्लाईओवर ब्रिज की मरम्मत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखा है। आदर्श नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी एक शिकायत में अवगत कराया गया था कि नगर पंचायत जलालाबाद स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 119 और रेलवे क्रॉसिंग संख्या 484 पर पूर्व में करोड़ों रुपए की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण यूपी सेतु निगम द्वारा कराया गया था और वर्तमान में पुल के एक्सपेंशन जॉइंट तथा अन्य जगहों पर गड्ढे हो गए हैं। इससे आम जनमानस का जीवन खतरे में है और जब इस संबंध में पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग और उत्तर प्रदेश सेतु निगम

में को अवगत कराया गया तो यह तय नहीं हो पा रहा है कि उक्त फ्लाईओवर ब्रिज किसके अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग का कहना है कि उक्त ब्रिज हमें अभी तक स्थानांतरित नहीं हुआ है और दोनों विभागों की लड़ाई में आम जनमानस पिस रहा है। उधर उक्त शिकायत के संबंध मे उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक शशिकांत ने रेलवे क्रॉसिंग पर बने फ्लाईओवर ब्रिज की मरम्मत के लिए देहरादून स्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखा है।

फास्ट न्यूज

समलैंगिक दोस्त के लिए कारोबारी ने किडनैपिंग का ड्रामा किया

आगरा। मुंबई के कपड़ा कारोबारी का आगरा में किडनैप हुआ। किडनैपर कार में उसे 60Km दूर हाथरस ले गए। 1.20 लाख रुपए लेकर छोड़ा। पुलिस तक ये मामला पहुंचने के सिर्फ 7 घंटे के अंदर चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। कारोबारी की किडनैपिंग नहीं हुई थी। वो आगरा के 'गे ग्रुप बॉटम' से जुड़ा हुआ था। वो अपनी मर्जी से अपने पार्टनर के साथ हाथरस गए थे।

आगरा में रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिक होंगे डिपोर्ट

आगरा। आगरा में अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस 10 जनवरी को सभी को अपनी कस्टडी में लेकर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होगी। वहां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) से समन्वय कर इन्हें बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक चोरी-छिपे सीमा पार कर आगरा में रह रहे थे।

रिटायर जेई...15 दिन शव सड़ता रहा, पत्नी-बेटियां नहीं आईं

कानपुर। कानपुर में सिंचाई विभाग से रिटायर जेई की करीब 15 दिन पहले मौत हुई, लेकिन किसी को पता नहीं चला। कारण यह कि पत्नी और दोनों बेटियां पैसों के झगड़े के चलते वाराणसी में अलग रहते थे। इन लोगों की आपस में बोलचाल तक बंद थी। 8 जनवरी को जब बहन रिटायर जेई के घर पहुंचीं, तब उनकी मौत का पता चला। इससे पहले 15 दिनों तक उनकी लाश बंद घर में सड़ती रही।

अवैध खनन पर प्रशासन की सख्ती, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

एसडीएम स्मृति मिश्रा के निर्देश पर तहसील व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

तमसा संकेत, संवाददाता

बिजनौर। जनपद बिजनौर की धामपुर उपजिलाधिकारी आईएएस स्मृति मिश्रा के निर्देशन में क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम मिलक जहांगीराबाद में अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा गया, जिसे आवश्यक कार्यवाही के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। एसडीएम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूतपुरी तिराहे पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा वाहनों की जांच की गई। इसके साथ ही जटपुरा चेकपोस्ट पर भी तहसीलदार द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में अवैध खनन में संलिप्त एक

अन्य ट्रैक्टर को भी मौके पर पकड़कर तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व लेखपालों की टीम द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। उपजिलाधिकारी स्मृति मिश्रा ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन द्वारा आगे भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे, ताकि सरकारी संसाधनों की अवैध लूट पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

भाजपा पार्षद डिप्टी सीएम से मिलेंगे, भ्रष्टाचार की फाइल लेकर जाएंगे लखनऊ

प्रभारी मंत्री नहीं सुलझा पाए मेयर-पार्षद विवाद

- नगर निगम के पार्षद 11 जनवरी को लखनऊ जाकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलेंगे।
- प्रभारी मंत्री ने दो बार दोनों पक्षों से बातचीत की। लेकिन मामला शांत नहीं हो सका है।

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर नगर निगम में चल रहा मेयर और पार्षदों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन दो बार लगातार बातचीत होने के बाद भी इस विवाद का हल नहीं निकल सका है।

पार्षदों के निलंबन के बाद शुरू हुआ था विवाद

कानपुर में 26 दिसंबर को नगर निगम का सदन हुआ था। यहां पर पार्षद पवन गुप्ता और पार्षद अंकित मौर्य अपनी बात रखना चाहते थे। मेयर ने उन्हें बोलने के लिए समय देने की बात कही थी, लेकिन दोनों के समय में अन्य पार्षद बोलने लगे थे। जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया था।

> पार्षद पवन गुप्ता ने बताया कि मेयर के पुत्र लगातार उन्हें धमका रहे हैं। जब वह प्रभारी मंत्री की बैठक में सर्किट हाउस पहुंचे थे, इसकी शिकायत उन्होंने प्रभारी मंत्री से की है।

मीटिंग में बंटी के पहुंचे पर उठे सवाल

प्रभारी मंत्री ने शनिवार को जब सर्किट हाउस में मीटिंग की तो यहां पर मेयर, पार्षदों के साथ भाजपा के पदाधिकारियों को बुलाया था। लेकिन इसमें मेयर प्रमिला पांडेय के पुत्र बंटी पांडेय भी पहुंचे थे। उनके पहुंचने पर भी पार्षदों ने सवालिया निशान लगाए हैं। पार्षदों का कहना है कि संगठन की बैठक में मेयर पुत्र का क्या काम था।

शनिवार को प्रभारी मंत्री ने की थी बैठक

उप्र सरकार के कैबिनेट मंत्री व कानपुर के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय दो बार पार्षदों और मेयर के बीच समझौते के लिए वार्ता करा चुके हैं। शनिवार को प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में दोनों पक्षों को बुलाया था और लगभग 5 घंटे तक वार्ता चलती रही थी। पार्षदों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन मंत्री इस विवाद को पूरी तरह से शांत नहीं करा पाए। अब पार्षद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए लखनऊ जाएंगे।

प्रयागराज में किसान ने कमरे में बंद किया, लोगों को देखकर गुर्राता रहा

घर में घुसा तेंदुआ 9 घंटे बाद पकड़ा गया

- तेंदुआ बेहोश है। उसको पिंजरे में डाल कर ले जाया गया है।
- वन विभाग की टीम कमरे के भीतर पहुंची। तेंदुए को ट्रेंकुलाइज किया गया।
- ट्रेंकुलाइज करने के समय तेंदुए ने वन विभाग की टीम पर छपट्टा भी मारा।

तमसा संकेत, एजेंसी

प्रयागराज। प्रयागराज में एक घर में तेंदुआ घुस गया। करीब 9 घंटे तक वह घर में ही घुसा रहा। इस दौरान खिड़की से देख रहे लोगों पर तेंदुआ गुर्राता रहा। इसी बीच कानपुर से आई डॉक्टरों की टीम घर में घुसी। फिर काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को ट्रेंकुलाइज किया गया। इस बीच, वन विभाग और 4 थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। वन विभाग ने घर के चारों तरफ जाल बिछा दिया। गांववालों की भी भीड़ लग गई। एहतियातन इलाके की घेराबंदी की गई। पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन के करीब 150 कर्मचारी-अफसर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। मामला झूंसी थाना क्षेत्र के छिबैया गांव का है। दरअसल, गुरुवार सुबह तेंदुआ गांव के पास एक तालाब के पास था। वहां कुछ लोगों ने उसे देखा। उसके बाद गांव के लोग जुट गए। इसी दौरान किसी ने तेंदुए को पत्थर मार दिया। इसके बाद तेंदुआ गुर्राते हुए भीड़ की तरफ मुड़ा, तो लोग जान बचाकर भागने लगे। तेंदुआ गांव की ओर भागा और चंद्रशेखर सिंह के घर में घुस गया। घर में चंद्रशेखर, 2 महिलाएं और 2 बच्चे थे। चंद्रशेखर सिंह ने बताया- मैंने किसी तरह अपने परिवार के सभी लोगों को घर से बाहर निकाला। इसके बाद तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए मौके पर दो पिंजरे मंगवाए गए हैं। मौके पर कानपुर चिड़ियाघर से डॉक्टरों की टीम पहुंची है। अब तेंदुए को ट्रंकुलाइज किया जाएगा और फिर उसे रेस्क्यू किया जाएगा।

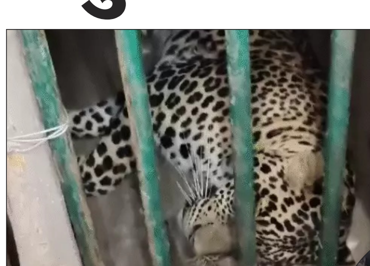

ट्रेंकुलाइज किया गया तेंदुआ

तेंदुआ ट्रेंकुलाइज करने से ठीक पहले खिड़की की ओर लपका। वन विभाग कर्मी पीछे हटे। इसके बाद अगले शॉट में ट्रेंकुलाइज हो गया। कमरे के अंदर अंधेरा होने से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है।अब तक तेंदुए को ट्रेंकुलाइज नहीं किया जा सका है।

ग्रामीणों से दूर हटने की अपील कर रहे वन विभाग के अफसर

वन विभाग के अफसर ग्रामीणों से दूर हटने की अपील कर रहे हैं। खिड़की के भीतर से ट्रेंकुलाइजर गन से फायर किया जा रहा है। पुलिस वन विभाग और जिला प्रशासन के लगभग डेढ़ सौ कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं।

डाइट फरीदपुर में पांच दिवसीय स्काउट एवं गाइड शिविर संपन्न

सेवा और अनुशासन में लिया व्यावहारिक प्रशिक्षण

तमसा संकेत, संवाददाता

बरेली। डाइट फरीदपुर में डी.एल.एड. 2023 बैच के प्रशिक्षुओं के लिए पांच दिवसीय स्काउट एवं गाइड विशेष परिचयात्मक शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य प्रशिक्षुओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना और सामाजिक दायित्व की भावना विकसित करना था।शिविर का शुभारंभ 05 जनवरी 2026 को डाइट की प्राचार्य श्रीमती दीप्ति वार्ष्णेय और वरिष्ठ प्रवक्ता श्री मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन डॉ. पुष्पकांत शर्मा और श्रीमती जमुनावती के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।पाँच दिवसीय शिविर के दौरान प्रशिक्षुओं को ड्रिल, प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन,

स्वच्छता अभियान, नेतृत्व विकास, समूह कार्य और सेवा संबंधी गतिविधियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षुओं ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ सभी गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाई। शिविर के अंतर्गत आयोजित कैंप फायर और सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं ने रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार टोली 'रानी लक्ष्मीबाई', द्वितीय पुरस्कार टोली 'दहाड़' और तृतीय पुरस्कार टोली 'गरुड़' को दिया गया। इसके अतिरिक्त टेंट डेकोरेशन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें सभी टोलियों ने स्वच्छता, सृजनात्मकता और कलात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया।दिनांक 09 जनवरी 2026 को आयोजित समापन समारोह में डाइट की प्राचार्य श्रीमती दीप्ति वार्ष्णेय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि प्रोफेसर विनम सक्सेना, विभाग—जंतु विज्ञान, बरेली कॉलेज, बरेली विशिष्ट अतिथि रहे। अतिथियों ने प्रशिक्षुओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और सक्रिय सहभागिता की सराहना की और उन्हें स्काउट एवं गाइड के आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

पृष्ठ 01 का शेष...

मेरे पास शाह के ...

इससे पहले शुक्रवार सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओ ब्रॉयन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान धक्का-मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से महाराष्ट्र में जनादेश चुरा लिया और अब वही तरीका बंगाल में अपनाना चाहती है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के खिलाफ जितनी चाहें उतनी एजेंसियों का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन बंगाल के लोग बीजेपी और दिल्ली के मालिकों के सामने नहीं झुकेंगे।ED ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें छह लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है। इनमें पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के DGP, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण कोलकाता) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) शामिल हैं। बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कल बंगाल में जो हुआ, वह आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा काम न सिर्फ़ अनैतिक, गैर-जिम्मेदार और असंवैधानिक है, बल्कि उन्होंने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा कि रेड निजी कंपनी के दफ्तर पर थी। हमें नहीं समझ आता कि इसमें ममता क्यों घबरा गई हैं। उन्हें डर है कि उनके घोटालों के राज खुल जाएंगे। प्रसाद ने कहा कि जांच को रोकना कानून का उल्लंघन है। ममता का हिसाब जनता करेगी।यह याचिका कानून प्रवर्तन और जांच से जुड़े मामलों के संबंध में दायर की गई है।

लव जिहाद का ...

उसने आरोप लगाया था कि उसके सीनियर डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। गर्भपात कराया और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। KGMU ने इस प्रकरण में बुधवार को विशाखा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। इसमें बताया गया कि डॉ. रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक को निष्कासित किया जाएगा। कुलपति सोनिया नित्यानंद ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। विशाखा कमेटी की रिपोर्ट पर यह एक्शन लिया गया है। DGME भी मामले में कार्रवाई करेगा। KGMU के ब्राउन हॉल में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुलपति ने आरोपी डॉ. रमीज मलिक के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में रमीज मलिक अब KGMU का हिस्सा नहीं रह सकता। यही कारण है कि अब यूनिवर्सिटी ने कठोरतम कार्रवाई की संस्तुति की है। इसके लिए विशाखा कमेटी के रिपोर्ट के आधार DGME को आज लेटर लिखा जा रहा जा है। बहुत जल्द उसे निष्कासित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले 22 दिसंबर को ही उसे सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद से ही कैंपस में उसकी एंट्री बैन है। लखनऊ KGMU में लव जिहाद के आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को ही कुर्की की कार्रवाई शुरू की थी। उसके लखनऊ, पीलीभीत और उत्तराखंड में तीन ठिकानों पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए। चौक पुलिस की टीमें लखनऊ के हुसैनाबाद स्थित फ्लैट, पीलीभीत के न्यूरिया स्थित पैतृक आवास और उत्तराखंड के खटीमा स्थित मकान पर पहुंचीं। तीनों जगहों पर कुर्की के नोटिस लगाए गए। पुलिस ने पीलीभीत और उत्तराखंड पुलिस से आरोपी की संपत्तियों का पूरा ब्योरा भी जुटाया। पुलिस का कहना है कि आरोपी रमीज लगातार फरार चल रहा है। यदि वह तय समय के भीतर सरेंडर नहीं करता है तो उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।

देश के 44% शहरों...

इसके बावजूद इन शहरों में से सिर्फ 4 प्रतिशत ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के दायरे में शामिल हैं। 2025 के आंकड़ों के अनुसार मेघालय का बर्नीहाट सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा, जहां PM2.5 का औसत 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। इसके बाद दिल्ली (96) और गाजियाबाद (93) दूसरे और तीसरे नंबर पर है। नोएडा चौथे स्थान पर है। लिस्ट में गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, हाजीपुर, मुजफ्फरनगर और हापुड़ भी शामिल हैं। सरकार ने प्रदूषित कम करने के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया था, लेकिन 7 साल बाद भी NCAP में सिर्फ 130 शहर शामिल हैं। इनमें से केवल 67 शहर ही उन 1,787 शहरों में आते हैं, जहां हर साल मानक से ज्यादा प्रदूषण रहता है। इस तरह NCAP फिलहाल भारत के केवल 4% लगातार प्रदूषित शहरों को ही कवर कर पा रहा है, जबकि ज्यादातर शहर इस योजना से बाहर हैं। NCAP में शामिल 28 शहरों में अब तक लगातार हवा की क्वालिटी मापने वाले स्टेशन (CAAQMS) नहीं लगाए गए हैं। जिन 102 शहरों में ये स्टेशन हैं, उनमें से 100 शहरों में PM10 का स्तर 80% या उससे ज्यादा दर्ज किया गया।

पूर्व आईपीएस ...

आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर कफ सिरप तस्करी में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। तहरीर में अंबरीश सिंह भोला ने बताया कि अमिताभ ठाकुर ने अपने एक्स हैंडल @amitabhthakur से 30 नवंबर को एक पत्र पोस्ट किया था, जिसमें उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर का नाम भी अंकित था। पत्र में दोनों को आजाद अधिकार सेना का अध्यक्ष और महासचिव बताया गया था। इस पत्र के साथ एक वीडियो भी साझा किया गया, जिसमें उनके खिलाफ कथित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए। अमिताभ ठाकुर की ओर से 23 दिसंबर को वाराणसी की जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। हालांकि, बनारस बार एसोसिएशन चुनाव के कारण सुनवाई टल गई थी। आज इसी अर्जी पर अमिताभ ठाकुर को जमानत मिली। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय, देवरिया में एक याचिका दायर की गई है। आजाद अधिकार सेना की ओर से सिंहासन चौहान ने यह याचिका दाखिल की है। इसमें यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) सहित छह अधिकारियों को नामजद किया गया है। इसमें मांग की गई है कि थाना कोतवाली, देवरिया को निर्देशित किया जाए कि वह नामजद अधिकारियों- आईपीएस अमिताभ यश, आईपीएस अमरेंद्र सेंगर, डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर विनीत सिंह, एसीपी कुलदीप दुबे और अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराए।

संसद का बजट...

आधिकारियों ने बताया कि आमतौर पर संसद शुक्रवार को स्थगित की जाती है, लेकिन 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे और उसके बाद वाले वीकेंड को ध्यान में रखते हुए, सत्र 2 अप्रैल को समाप्त हो सकता है। बजट सत्र में अवकाश से संबंधित स्टैंडिंग कमेटियों को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों की जांच करने का समय मिलता है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चला था। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा से VB-G RAM G सहित 8 बिल पास किए गए। 2 बिल संसदीय कमेटी को भेजे गए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया था सत्र की शुरुआत रवींद्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और अंत महात्मा गांधी के अपमान के साथ हुआ।

5 दिन में आईसीसी को दूसरी चिट्ठी लिखी, मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने पर विवाद

बांग्लादेश ने फिर भारत से मैच शिफ्ट करने को कहा

मांग

नई दिल्ली, एजेंसी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को 5 दिन में दूसरा पत्र भेजकर टी-20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत की बजाय श्रीलंका में कराने की मांग की है। बोर्ड ने इसके पीछे सुरक्षा संबंधी चिंताओं को कारण बताया है। इससे पहले 4 जनवरी को पहली बार ICC से वर्ल्ड कप मैच के वेन्यू बदलने की अपील की गई थी। ICC ने अब तक इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उसने BCB से यह स्पष्ट करने को कहा है कि सुरक्षा को लेकर असल चिंता क्या है। वहीं, BCB के अंदर भी मतभेद सामने आ रहे हैं। एक धड़ा आसिफ नजरुल के कठोर रुख का समर्थन

कर रहा है। दूसरा धड़ा ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के साथ बातचीत जारी रखने के पक्ष में है। उनका मानना है कि अगर पुख्ता और बेहतर सुरक्षा इंतजाम किए जाएं, तो समस्या का समाधान हो सकता है। टी-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ग्रुप-सी में रखा गया है। टीम 7 फरवरी को वेस्टइंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड से भिड़ने वाली हैं।

टी-20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होना है। बांग्लादेश को ग्रुप लीग में कुल चार मैच खेलने हैं, जिनमें से तीन मैच कोलकाता और एक मैच मुंबई में तय हैं। लेकिन बांग्लादेश टीम ने अब तक भारत जाने से इनकार कर दिया है, जिससे टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही उनकी भागीदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं।

बांग्लादेश सरकार की सख्त भूमिका

रिपोर्ट्स के मुताबिक,यह ताजा पत्र खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल के साथ चर्चा के बाद भेजा गया है। नजरुल इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। एक सूत्र ने समाचार एजेंसी PTI को बताया,'ICC ने सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का पूरा ब्योरा मांगा था, जिसे BCB ने विस्तार से साझा किया है।' हालांकि, इन चिंताओं का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है।

बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर बैन लगाया

KKR से मुस्तफिजुर को रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां की सरकार ने IPL के प्रसारण पर बैन लगा दिया। साथ ही भारत में वर्ल्ड कप मैच खेलने से भी इनकार कर दिया और ICC को वेन्यू बदलने के लिए ई-मेल भेजा था। वहीं टीम का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल से होना है।

क्या है पूरा विवाद?

16 दिसंबर को IPL मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के कारण भारत में मुस्तफिजुर का विरोध होने लगा। अब तक वहां 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है।

श्रीलंका के बैटिंग कोच बने विक्रम राठौर

18 जनवरी से 10 मार्च तक जिम्मेदारी संभालेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी

टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर अब श्रीलंका के बैटिंग कोच बन गए हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने बताया कि टी-20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए राठौर को सलाहकार कमेटी का हिस्सा बनाया। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। राठौर 18 जनवरी से 10 मार्च तक श्रीलंका टीम के साथ रहेंगे। भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर भी श्रीलंका टीम के साथ जुड़े हैं। उन्हें पिछले महीने ही टीम ने कोचिंग सेट-अप का हिस्सा बनाया था। श्रीधर और राठौर दोनों को ही वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम के साथ जोड़ा गया। ICC टूर्नामेंट खत्म होने के बाद दोनों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। भारत के ही आर श्रीधर श्रीलंका के फील्डिंग कोच भी हैं। राठौर सितंबर 2019 से जुलाई

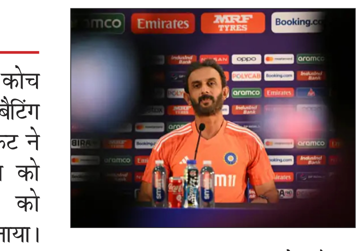

2024 तक टीम इंडिया के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। इस दौरान रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ टीम के हेड कोच रहे। फिलहाल राठौर IPL टीम राजस्थान रॉयल्स में लीड असिस्टेंट कोच की भूमिका भी निभा रहे हैं। 2014 की टी-20 वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका इस बार ग्रुप-बी में है। टीम को आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और ओमान के ग्रुप में रखा गया। श्रीलंका में 14 साल बाद ICC टूर्नामेंट होगा, 2012 में आखिरी बार यहां टी-20 वर्ल्ड कप ही खेला गया था। तब वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को ही फाइनल हराकर टाइटल जीता था।

नाइट क्लब विवाद पर इंग्लिश कप्तान ब्रूक ने माफी मांगी

वेलिंगटन वनडे से पहले शराब पी, बाउंसर से झगड़ा भी हुआ

नई दिल्ली, एजेंसी

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने न्यूजीलैंड दौरे के दौरान एक नाइट क्लब में हुए विवाद को लेकर माफी मांगी है। यह घटना न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले की रात 31 अक्टूबर 2025 को हुई थी। यह मामला गुरुवार को सामने आया है। जब घटना वाली रात का एक वीडियो लीक हुआ। इसमें ब्रूक और जैकब बेथेल दोनों शराब पीते दिखे। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, वेलिंगटन वनडे से एक रात पहले हैरी ब्रूक को एक क्लब में एंट्री नहीं दी गई। इसके बाद बाउंसर ने उन्हें मारा। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया में 4-1 से एशेज सीरीज हार चुकी है और टीम

के कल्चर पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रूक इस समय इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम के कप्तान हैं और टेस्ट टीम के उपकप्तान भी हैं। हालांकि, कप्तानी बरकरार रखते हुए उन पर करीब 30 हजार पाउंड का जुर्माना लगाया गया है और आखिरी चेतावनी दी गई है। वे टी-20 वर्ल्ड कप 2026 और 2 हफ्ते बाद शुरू होने वाली श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर्स की सीरीज तक इंग्लैंड की कप्तानी करते रहेंगे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने कहा- 'इस घटना को औपचारिक और गोपनीय अनुशा-सनात्मक प्रक्रिया के तहत निपटा लिया गया है और खिलाड़ी ने माना है कि उसका व्यवहार मानकों के अनुरूप नहीं था।' ECB के क्रिकेट डायरेक्टर रॉब की ने बताया कि उन्होंने न्यूजीलैंड में ब्रूक और बेथेल के व्यवहार को लेकर उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि यह औपचारिक चेतावनी देने लायक नहीं था, लेकिन अनौपचारिक तौर पर समझाना जरूरी था। ECB के मुख्य कार्यकारी रिचर्ड गोल्ड ने कहा कि एशेज सीरीज में टीम के 'व्यवहार' की भी जांच होगी। BBC के अनुसार इंग्लिश खिलाड़ियों ने दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच मिले ब्रेक में अत्यधिक शराब का सेवन किया था।

सात्विक-चिराग क्वार्टरफाइनल में, मेन्स सिंगल्स में भारतीय चुनौती खत्म

पीवी सिंधु मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचीं

कुआलालंपुर, एजेंसी

कुआलालंपुर में चल रहे BWF सुपर 1000 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की स्टार शटलर और दो बार की ओलिंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं, मेंस डबल्स में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी क्वार्टरफाइनल में पहुंच गई है। शुक्रवार को खेले गए क्वार्टरफाइनल में सिंधु ने जापान की तीसरी सीड अकाने यामागुची का सामना किया। सिंधु ने सिर्फ 11 मिनट में पहला गेम 21-11 से अपने नाम किया। इसके बाद यामागुची घुटने की चोट के कारण मैच से हट गईं (रिटायर्ड

हर्ट), जिससे सिंधु को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। वहीं, आयुष शेट्टी ने विश्व नंबर-1 और टॉप सीड शी यू क्वी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 18-21, 21-18, 12-21 से मैच गंवा बैठे। लक्ष्य सेन को हॉन्गकॉन्ग-चाइना के ली चेउक यिउ से 20-22, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल मुकाबलों में युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने विश्व नंबर-1 और टॉप सीड चीन के शी यू क्वी को कड़ी चुनौती दी, लेकिन तीन गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में उन्हें 18-21, 21-18, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं, भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन का सफर भी क्वार्टरफाइनल में समाप्त हो गया। लक्ष्य को हॉन्गकॉन्ग-चाइना के ली चेउक यिउ के खिलाफ सीधे गेमों में 20-22, 15-21 से पराजय झेलनी पड़ी।

सिंधु ने जापान की आठवीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी टोमोका मियाजाकी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था।

राउंड ऑफ 16 में भी आसान जीत

इससे पहले गुरुवार को राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान की आठवीं सीड टोमोका मियाजाकी को 33 मिनट में 21-8, 21-13 से हराया था। मेन्स सिंगल्स में भारतीय चुनौती खत्म हो गई है। लक्ष्य सेन और युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी प्री-क्वार्टरफाइनल में हारकर बाहर हो गए।

सात्विक-चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में

मेंस डबल्स में भारत की टॉप जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मलेशिया की जुनैदी अरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-18, 21-11 से हराया। 39 मिनट चले मुकाबले में भारतीय जोड़ी का दबदबा साफ दिखा। अब क्वार्टरफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की छठी सीड जोड़ी फजर अल्फियन और मुहम्मद रियन अर्दियांतो से होगा।

मनोरंजन

गाने के रिलीज होते ही कई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बनाकर वरुण धवन के फेशियल एक्सप्रेशन का मजाक उड़ाया। इन वीडियोज में उनके अभिनय को ओवरएक्टिंग बताते हुए आलोचना की गई, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया।

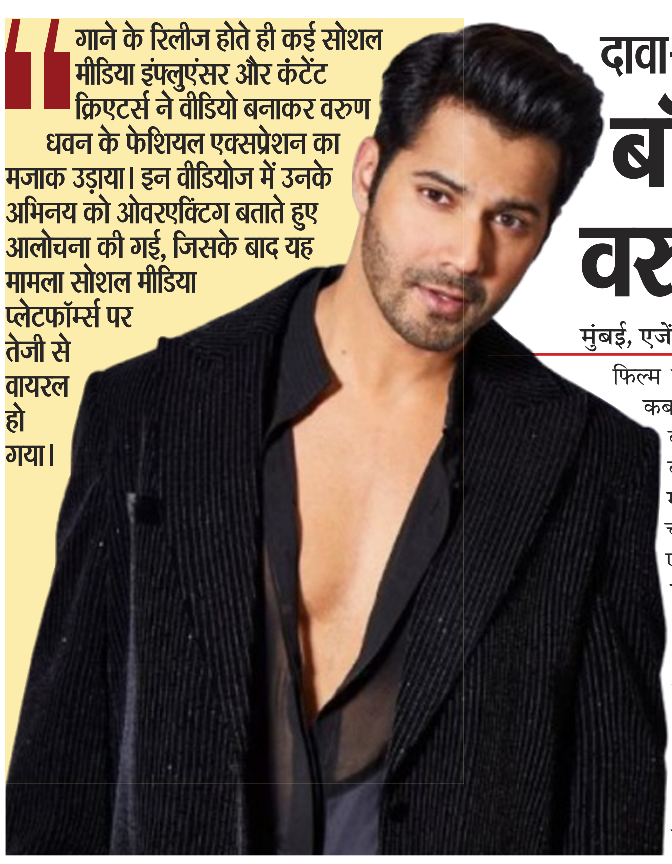

दावा- निगेटिव पीआर कैंपेन के जरिए किया गया टारगेट, एक्टर ने भी दिया रिएक्शन

बॉर्डर-2 के गाने के लिए वरुण धवन का उड़ा मजाक

मुंबई, एजेंसी

फिल्म बॉर्डर 2 का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज होने के बाद से अभिनेता वरुण धवन सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। जहां एक ओर गाने को दर्शकों का एक वर्ग भावनात्मक और देशभक्ति से जुड़ा बता रहा है, वहीं दूसरी ओर वरुण धवन के एक्सप्रेशन और अभिनय को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर तीखी आलोचनाओं और ट्रोलिंग का सामना

करना पड़ रहा है। स्क्रीनशॉट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन सोशल मीडिया पेजों की इंगेजमेंट अच्छी है और जिनकी ऑडियंस बोल्ड व अनफिल्टर्ड ओपिनियन पसंद करती है, उनके साथ कोलैब करने की योजना बनाई गई है।

वायरल चैट में लिखा गया है कि बॉर्डर 2 को लेकर एक सुनियोजित पीआर कैंपेन चलाया जा रहा है, जो फिल्म से जुड़े निगेटिव कमेंट्स पर आधारित है। इस कैंपेन का मकसद वरुण धवन के परफॉर्मेंस चॉइस, स्क्रीन प्रेजेंस, फेशियल एक्सप्रेशन और इस सवाल पर बहस खड़ी करना बताया गया है कि क्या वरुण धवन जैसी बड़ी फिल्म और उसकी विरासत के लिए सही कास्टिंग हैं या नहीं।

पेड ट्रोलिंग के आरोप, रेडिट पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट

इसी बीच रेडिट पर एक कथित चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया है, जिसने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। इस स्क्रीनशॉट को लेकर दावा किया जा रहा है कि वरुण धवन को टारगेट करने के लिए एक पेड पीआर ट्रोलिंग कैंपेन चलाया गया है।

प्वाइंटेड अटैक की रणनीति का दावा

वायरल चैट में आगे उन प्वाइंट्स का भी जिक्र है, जिनके आधार पर वरुण धवन को ऑनलाइन टारगेट किया जाना था।

सरोजिनी नायडू की बायोपिक का ट्रेलर रिलीज

फिल्म के राइटर बोले- राजनैतिक नहीं उनके जीवन पर आधारित

मुंबई, एजेंसी

महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी पर बनी पहली हिंदी फिल्म 'सरोजिनी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 'सरोजिनी' का ट्रेलर मुंबई में एक शानदार समारोह में रिलीज किया गया जिसमें फिल्म की पूरी कास्ट क्रू मौजूद थी। फिल्म को विनय चंद्रा ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने इसका संगीत भी दिया है। फिल्म की पटकथा और संवाद धीरज मिश्रा ने लिखी हैं कलाकारों की बात करें तो मुख्य कलाकारों में इंद्रा तिवारी, सोनल, हितेन तेजवानी, जरीना वहाब हैं। फिल्म के लेखक धीरज मिश्रा बॉलीवुड में लगातार सक्रिय हैं उन्होंने कई देश भक्ति और

बायोपिक फिल्में लिखी हैं। फिल्म के लेखक धीरज के मुताबिक, 'फिल्म में सरोजिनी नायडू के जीवन को बड़ी सहजता के साथ दिखाया गया है। फिल्म राजनैतिक न हो कर एक पिता-पुत्री के संबंध, एक महान कवयित्री जिन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव के अतिरिक्त सरोजिनी के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित हैं।'

प्रिंस नरूला ने बताई गिरफ्तारी के वायरल वीडियो की सच्चाई

एक्टर बोले- वीडियो ब्रांड शूट का हिस्सा था, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया

मुंबई, एजेंसी

एक्टर प्रिंस नरूला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें पुलिस के साथ ले जाते हुए देखा जा रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस ने प्रिंस को गिरफ्तार किया है। हालांकि, एक्टर ने गुरुवार को इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए इस खबर को गलत बताया है। टेलीचक्कर से बात करते हुए प्रिंस ने इस वीडियो को लेकर कहा, "यह एक ब्रांड शूट का हिस्सा था। मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है।" उन्होंने साफ किया कि वायरल वीडियो किसी शूट का सीन था। दरअसल, प्रिंस का जो वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि एक्टर को दिल्ली में एक मस्जिद (अवैध निर्माण) हटाने के दौरान हुए विवाद के संबंध में या भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

प्रिंस को टीवी इंडस्ट्री में रियलिटी शो के किंग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े रियलिटी शो जीतकर पहचान बनाई है। प्रिंस साल 2015 में MTV रोडीज X2 के विनर रहे। उसी साल उन्होंने MTV स्प्लिट्सविला 8 भी जीता। फिर 2015-16 में उन्होंने बिग बॉस 9 जीतकर जीत की हैट्रिक पूरी की। साल 2019 में उन्होंने अपनी पत्नी युविका चौधरी के साथ नच बलिए 9 जीता। एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने टीवी शो बढ़ो बहू में लीड रोल निभाया था। वह लंबे समय तक MTV रोडीज के साथ एक गैंग लीडर के तौर पर भी जुड़े रहे हैं।

तारा सुतारिया और वीर पहारिया का ब्रेकअप

रिपोर्ट में रिलेशनशिप खत्म होने का दावा, दोनों एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में थे

मुंबई, एजेंसी

बॉलीवुड अभिनेत्री तारा सुतारिया और अभिनेता वीर पहारिया के रिश्ते को लेकर एक बार फिर सुर्खियां तेज हो गई हैं। इंडस्ट्री से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया है। मनोरंजन वेबसाइट फिल्मफेयर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तारा और वीर अब साथ नहीं हैं, हालांकि दोनों में से किसी ने भी अब तक इस खबर पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक तारा सुतारिया और वीर पहारिया की डेटिंग की शुरुआत साल 2025 की शुरुआत में हुई थी। शुरुआती दिनों में दोनों ने अपने रिश्ते को निजी रखा, लेकिन जल्द ही उन्हें कई बार एक साथ स्पॉट किया गया। कभी डिनर डेट तो कभी निजी आयोजनों में साथ नजर आने के बाद उनके अफेयर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। मार्च 2025

में दोनों एक हाई-प्रोफाइल फैशन इवेंट में साथ पहुंचे थे, जहां उनकी कैमिस्ट्री ने सभी का ध्यान खींचा था। इसके अलावा गणेश चतुर्थी के मौके पर भी दोनों की साथ मौजूदगी ने उनके रिश्ते की पुष्टि जैसी स्थिति बना दी थी। हालांकि, वायरल वीडियो को लेकर बाद में सफाई भी सामने आई। तारा सुतारिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए झूठी खबरें फैलाने और पेड पीआर के जरिए नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया था। वहीं, वीर पहारिया ने भी स्पष्ट किया था कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उनका रिएक्शन उस गाने का नहीं था, बल्कि किसी और गाने के दौरान का था, जिसे गलत तरीके से एडिट कर पेश किया गया।

कॉन्सर्ट वीडियो से बढ़ी थी चर्चा

दिसंबर 2025 के अंत में मुंबई में एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें तारा सुतारिया सिंगर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती दिखीं। परफॉर्मेंस के दौरान एपी द्वारा तारा को गले लगाने और गाल पर किस करने का वीडियो चर्चा में आ गया था। इसी कॉन्सर्ट में दर्शकों के बीच मौजूद वीर पहारिया का रिएक्शन भी वायरल हुआ था, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए गए।

अब अलग होने की खबर

अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि तारा और वीर ने आपसी सहमति से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। हालांकि, ब्रेकअप की असली वजह अभी सामने नहीं आई है। इसी कॉन्सर्ट में दर्शकों के बीच मौजूद वीर पहारिया का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कुछ यूजर्स ने वीडियो के आधार पर दावा किया कि वीर इस दौरान असहज और नाराज नजर आ रहे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। कई लोगों ने इस घटना को तारा और वीर के रिश्ते से जोड़कर देखा।

बताया जा रहा है कि तारा और वीर की डेटिंग की शुरुआत साल 2025 की शुरुआत में हुई थी। दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया, जिससे उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। मार्च 2025 में दोनों एक फैशन इवेंट में साथ नजर आए थे, वहीं गणेश चतुर्थी के दौरान भी उनकी साथ मौजूदगी ने सुर्खियां बटोरी थीं।

बिना आदेश हमले का जवाब देंगे सैनिक, ग्रीनलैंड में सभी को ₹90 लाख दे सकते हैं ट्रम्प

पहले गोली चलाएंगे, बाद में बात करेंगे : डेनमार्क

धमकी

कोपनहेगन, एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी के बीच डेनमार्क ने सख्त रुख अपनाया है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई विदेशी ताकत हमारे इलाके पर हमला करती है, तो सैनिक बिना कमांडर के आदेश का इंतजार किए बिना तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे और गोली चलाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बिना आदेश हमला करने का नियम 1952 का है। दरअसल, 1952 में डेनमार्क ने अपनी सेना के लिए एक नियम बनाया था, जिसके मुताबिक विदेशी ताकतों के देश पर हमला करने की स्थिति में सैनिकों को तुरंत लड़ना होगा। इसके लिए उन्हें किसी सीनियर अधिकारी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। यह नियम पहली बार 1940 में तब लागू हुआ था जब जर्मनी ने डेनमार्क पर हमला किया था। उस समय कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया था और सैनिकों को समझ नहीं आया था कि क्या किया जाए। डेनमार्क ने इसी का हवाला देते हुए कहा कि वह नियम आज भी लागू है। अमेरिकी अधिकारी ग्रीनलैंड के हर निवासी को 9 लाख से 90 लाख तक की एकमुश्त राशि देने की योजना पर चर्चा कर रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के अधिकारी इस विचार पर बात कर रहे हैं, हालांकि रकम अभी स्पष्ट नहीं हैं। ग्रीनलैंड की आबादी करीब 57,000 है, इसलिए अगर हर व्यक्ति को 90 लाख रुपए दिए जाएं तो कुल खर्च लगभग 53,900 से 54,050 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है। वहीं अमेरिकी मीडिया द न्यू यॉर्क टाइम्स (NYT) ने विशेषज्ञों के हवाले से बताया कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए अमेरिका को इसे खरीदने या उसपर जबरन कब्जा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, "अगर अमेरिका अच्छे से बात करे, तो उसे लगभग सब कुछ मिल सकता है।" लेकिन ग्रीनलैंड को खरीदना पूरी तरह अलग बात है, क्योंकि ग्रीनलैंड के लोग इसे बेचे जाने के खिलाफ हैं। डेनमार्क के पास इसे बेचने का अधिकार नहीं है। पहले के समय में ग्रीनलैंड से जुड़ा फैसला डेनमार्क ही लेता था। अब स्थिति बदल गई है, क्योंकि ग्रीनलैंड के लोगों को स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह करने का अधिकार है और डेनिश अधिकारियों ने कहा है कि द्वीप के 57,000 निवासियों पर इसका फैसला छोड़ दिया गया है। इस समझौते की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जब डेनमार्क नाजी कब्जे में था।

रिपोर्ट- ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए अमेरिका को इसे खरीदने की जरूरत नहीं

ग्रीनलैंड में डेनमार्क की सैन्य इकाई जॉइंट आर्कटिक कमांड यह तय करेगी कि कोई कार्रवाई हमला मानी जाएगी या नहीं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रम्प बार-बार ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की मांग कर रहे हैं। साथ ही जरूरत पड़ने पर सैनिकों को भेजने की धमकी दे रहे हैं।

ग्रीनलैंड में स्थित पिटुफिक एयरबेस, जिसे पहले थुले वायु अड्डा के नाम से जाना जाता था।

रक्षा समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में काफी छूट मिली है

1951 के एक पुराने रक्षा समझौते के तहत अमेरिका को पहले से ही ग्रीनलैंड में काफी छूट मिली हुई है। यह समझौता अमेरिका और डेनमार्क के बीच हुआ था। कोपेनहेगन स्थित डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के शोधकर्ता मिकेल रुंगे ओलेसेन ने NYT से कहा कि अमेरिका के पास ग्रीनलैंड में इतनी स्वतंत्रता है कि वह वहां लगभग जो चाहे कर सकता है।

अमेरिका पिटुफिक स्पेस बेस से ग्रीनलैंड में मिसाइल ट्रैकिंग करता है

पिछले साल एक सर्वे में 85 प्रतिशत लोगों ने अमेरिकी कब्जे का विरोध किया था। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नीलसन ने बार-बार कहा है कि "हमारा देश बिकाऊ नहीं है।" 1951 का छोटा रक्षा समझौता 2004 में अपडेट किया गया, जिसमें ग्रीनलैंड की सेमी-ऑटोनॉमस सरकार को शामिल किया गया, ताकि अमेरिकी सैन्य गतिविधियां स्थानीय लोगों को प्रभावित न करें।

फास्ट न्यूज

अमेरिका ने रूस का जहाज जब्त किया

मॉस्को/ वॉशिंगटन। अमेरिका ने बुधवार को वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे 2 टैंकरों को पकड़ लिया। न्यूज एजेंसी 'रशिया टुडे' के मुताबिक इसमें से एक रूस का जहाज मैरिनेरा है, जबकि दूसरे का नाम सोफिया है। सोफिया पर पनामा देश का झंडा है, लेकिन यह किस देश का है इसकी जानकारी नहीं है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया।

सेंसेक्स 664 अंक गिरा, 83,516 पर आया

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 9 जनवरी को गिरावट है। सेंसेक्स 664 अंकों की गिरावट के साथ 83,516 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 220 अंकों की गिरावट है। यह 25,656 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आज के कारोबार में रियल्टी और फॉर्मा शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट है। निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स करीब 2.50% नीचे हैं। वहीं फार्मा इंडेक्स 1% नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं आईटी शेयरों में तेजी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.30% ऊपर है।

16 जनवरी को आएंगे रिलायंस के क्यू3 नतीजे

मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने अपनी तीसरी तिमाही (Q3) के नतीजों की तारीख का ऐलान कर दिया है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स 16 जनवरी को होने वाली बैठक में 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुई तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा करेंगे और उन्हें मंजूरी देंगे। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, बोर्ड मीटिंग के बाद एक एनालिस्ट मीट भी आयोजित की जाएगी, जिसमें चालू वित्त वर्ष के नौ महीनों के प्रदर्शन पर चर्चा होगी।

भारत कोकिंग कोल का आईपीओ आज से खुला

50% प्रीमियम के संकेत, प्राइस बैंड ₹21 से ₹23 प्रति शेयर

मुंबई, एजेंसी

भारत कोकिंग कोल (BCCL) का आईपीओ आज 9 जनवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। ये नए साल का पहला बड़ा पब्लिक ऑफर है। ये कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी है। ग्रे मार्केट में यह शेयर अपने इश्यू प्राइस से 50% ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसकी मजबूत लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। ये कंपनी स्टील सेक्टर के लिए जरूरी 'कोकिंग कोल' बनाती है। यह पूरा आईपीओ 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) है, यानी इसके जरिए मिलने वाला पैसा सीधे प्रमोटर कंपनी कोल इंडिया के पास जाएगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 21 से 23 प्रति शेयर तय किया है। निवेशक कम से कम 600 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए ऊपरी स्तर पर 13,800 निवेश करने होंगे। यह इश्यू 13 जनवरी तक खुला रहेगा। अगर आप फोनपे, गूगल-पे या पेटीएम इस्तेमाल करते हैं और आपके पास पहले से जिरोधा, ग्रो जैसे ब्रोकर के पास डिमैट अकाउंट है तो ये आसानी से हो जाएगा। एप में जाएं और 'BCCL IPO' सर्च करें। डिटेल्स भरें और UPI आईडी डालकर पेमेंट अप्रूव कर दें। IPO में शेयरों का अलॉटमेंट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिए होता है, जिसमें आवेदन करने वाले सभी निवेशकों के नाम रैंडम तरीके से चुने जाते हैं।

जमीनी हमले कर इन्हें खत्म करेंगे, मेक्सिको की राष्ट्रपति बोलीं- अमेरिका कहीं का मालिक नहीं

मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल्स का राज चल रहा : ट्रम्प

वॉशिंगटन, एजेंसी

वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को कहा कि उनका प्रशासन जल्द ही जमीन पर मौजूद ड्रग कार्टेल को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि मेक्सिको पर ड्रग कार्टेल का राज है। यह अमेरिका में हर साल 2.5 लाख से 3 लाख लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि समुद्र के रास्ते से ड्रग्स की तस्करी को 97% तक रोक दिया है, इसलिए अब जमीन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने योजनाओं के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने ट्रम्प के बयानों का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अमेरिका किसी भी क्षेत्र का मालिक नहीं है। शीनबॉम ने जोर देकर कहा कि मेक्सिको एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है। यहां सहयोग तो किया जा सकता है, लेकिन हस्तक्षेप नहीं। उन्होंने ड्रग तस्करी रोकने में दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग का जिक्र किया, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को सिरे से नकार दिया। ट्रम्प ने अक्टूबर 2025 में कहा था कि वो ड्रग तस्करी से निपटने के लिए मेक्सिको में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये दावा अमेरिकी न्यूज चैनल NBC न्यूज की रिपोर्ट में किया गया था। रिपोर्ट में दो मौजूदा और दो रिटायर्ड अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक अभी ट्रम्प प्रशासन मिशन के दायरे और कार्रवाई करने के अधिकारों पर चर्चा कर रहा है।

हवाई हमलों और ड्रोन स्ट्राइक का प्लान

NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऑपरेशन में अमेरिका की ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड (JSOC) की टीमें शामिल हो सकती हैं, जो CIA के अधिकार क्षेत्र में काम करेंगी। मिशन के तहत ड्रग लैब्स और कार्टेल सरगनाओं को निशाना बनाने के लिए ड्रोन स्ट्राइक की योजना है। कई ड्रोन ऐसी हैं जिनके संचालन के लिए जमीन पर भी ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है।

ड्रग्स तस्कर गिरोहों को आतंकी संगठन घोषित किया था

फरवरी 2025 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने 6 मेक्सिकन कार्टेल्स, MS-13 गैंग और वेनेजुएला के 'ट्रेन डे अरागुआ' को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। इससे अमेरिकी सेना और CIA को गुप्त ऑपरेशंस करने की खुली छूट मिल जाती है। ट्रम्प पहले भी कह चुके हैं कि उन्होंने वेनेजुएला में CIA को कार्रवाई की मंजूरी दी थी और जरूरत पड़ने पर वे कार्टेल्स को जमीन पर भी निशाना बनाएंगे।

शीनबॉम बोली- हम स्वतंत्र देश, हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने साफ किया कि मेक्सिको दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को पूरी तरह खारिज करता है। ट्रम्प ने दावा किया कि उन्होंने शीनबॉम से कई बार अमेरिकी सैनिक भेजकर कार्टेल्स को खत्म करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया।

ट्रम्प के इशारों पर चल रही वेनेजुएला की सरकार

कहा- यहां से तेल निकालकर दुनिया को बेचेंगे

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को कहा कि अमेरिका अब वेनेजुएला को चलाएगा और उसके विशाल तेल भंडार से सालों तक तेल निकालेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रम्प ने बताया कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार "जो भी जरूरी है, वह सब दे रही है।" जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका कितने समय तक वेनेजुएला पर सीधा कंट्रोल रखेगा। क्या यह तीन महीने होगा? छह महीने? एक साल? या उससे भी अधिक? इसपर उन्होंने कहा, 'यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह काफी लंबा समय होगा, शायद सालों तक।' ट्रम्प ने वेनेजुएला में चुनाव कब होंगे, इस पर कोई जानकारी नहीं दी। अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को लेकर भी ट्रम्प ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। ट्रम्प ने कहा, मैं आपको यह नहीं बता सकता। ट्रम्प ने कहा कि वह भविष्य में वेनेजुएला की यात्रा करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि ऐसा समय जल्द आएगा जब मेरा वहां जाना सुरक्षित हो जाएगा।" ट्रम्प से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल की बिक्री को अनिश्चित काल तक अपने कंट्रोल में रखेगा। रिपब्लिकन सांसदों ने ज्यादातर इस कदम का समर्थन किया है, लेकिन डेमोक्रेट्स ने चेतावनी दी है कि बिना स्पष्ट कानूनी अधिकार के अमेरिका एक लंबे अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की ओर बढ़ रहा है। इंटरव्यू में ट्रम्प ने मादुरो की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला की नई नेता मानने के सवाल का जवाब नहीं दिया, जबकि विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो, जिनकी पार्टी ने 2024 के चुनाव में जीत हासिल की थी और हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार जीता, को समर्थन नहीं देने का कारण भी नहीं बताया।

चलती गाड़ी से पुलिसकर्मी को गोली मारी

दो दिन में दूसरे पुलिस अफसर की हत्या, देश भर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी

तेहरान, एजेंसी

ईरान में आर्थिक संकट को लेकर चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच बुधवार को एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना ईरान के दक्षिण-पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में हुई। वीडियो में एक अज्ञात हमलावर चलती गाड़ी से बाहर झुककर लगातार फायरिंग करता है। वीडियो में सिर्फ बंदूक का सिरा दिखाई देता है। गोलियां लगने के बाद पुलिस की गाड़ी सड़क से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मारे गए पुलिस अधिकारी की पहचान महमूद हकीकत के रूप में हुई है। यह पिछले दो दिनों में ईरान में मारे गए दूसरे पुलिसकर्मी की घटना है। इससे पहले मंगलवार को एहसान अगाजानी नाम के एक पुलिस अधिकारी की पश्चिमी ईरान के इलाम प्रांत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे मालेकशाही इलाके में झड़पों के दौरान घायल हुए थे और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हालांकि, ईरान के मुख्य न्यायाधीश गोलामहुसैन मोहसनी एजई ने चेतावनी दी है कि इस्लामिक रिपब्लिक के दुश्मनों की मदद करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ईरान ने पड़ोसी देशों और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की है, जैसे कि INSTC कॉरिडोर और चीन के साथ नए ट्रांजिट रूट्स। फिर भी, 2025 में जीडीपी वृद्धि केवल 0.3% रहने का अनुमान है। प्रतिबंध हटने या परमाणु समझौते की बहाली के बिना व्यापार और रियाल का मूल्य स्थिर करना मुश्किल रहेगा।

ईरानी पुलिसकर्मी को गोली मारने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी

ईरान में पिछले महीने से सरकार के खिलाफ तेज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह पिछले तीन सालों में सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। विरोध की शुरुआत तब हुई जब तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार के दुकानदारों ने गिरती मुद्रा (रियाल) के विरोध में दुकानें बंद कर दीं। इसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लोग आर्थिक बदहाली, सरकारी कुप्रबंधन, पश्चिमी प्रतिबंधों और राजनीतिक व सामाजिक आजादी पर पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।

ईरान की इकोनॉमी तेल निर्यात पर निर्भर

साल 2024 में ईरान का कुल निर्यात लगभग 22.18 बिलियन डॉलर था, जिसमें तेल और पैट्रोकैमिकल्स का बड़ा हिस्सा था, जबकि आयात 34.65 बिलियन डॉलर रहा, जिससे व्यापार घाटा 12.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

विवाद : अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर बोले- ट्रम्प ने ईगो पर लिया, अब पुराने ऑफर खत्म

मोदी ने ट्रम्प को कॉल नहीं किया, इसलिए रुकी ट्रेड-डील

वॉशिंगटन, एजेंसी

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि भारत के साथ डील किसी पॉलिसी विवाद की वजह से नहीं रुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सीधे फोन न करना इसकी वजह है। लुटनिक के मुताबिक ट्रम्प चाहते थे कि मोदी खुद उनसे बात करके डील फाइनल करें, लेकिन ऐसा न होने पर ट्रम्प ने इसे अपने 'ईगो' पर ले लिया। लुटनिक ने ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने समय सीमा खत्म होने से पहले खुद ट्रम्प को फोन किया और अगले ही दिन डील का ऐलान हो गया। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो शर्तें पहले तय हुई थीं, अब वे खत्म हो चुकी हैं। लुटनिक ने साफ कहा, 'अमेरिका अब उस ट्रेड डील से पीछे हट गया है, जिस पर हम पहले सहमत हुए थे। हम अब उस पुराने ऑफर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अगर अब बातचीत होती है, तो भारत को नई और शायद कठिन शर्तों का सामना करना पड़ सकता है।

> “ जानकारों का मानना है कि भारत को ट्रम्प के 'ईगो' को ठेस पहुंचने का खामियाजा भुगतना पड़ा। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर ट्रम्प ने टैरिफ पहले 25% और फिर इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। हालांकि, 17 सितंबर को मोदी के जन्मदिन पर ट्रम्प के कॉल के बाद बर्फ कुछ पिघली। दोनों नेताओं ने दिवाली और दिसंबर में भी बात की है, लेकिन ट्रेड डील अभी भी अधर में है।

'डील तैयार थी, मोदी को बस एक फोन करना था'

एक पॉडकास्ट में लुटनिक ने बताया कि भारत के साथ ट्रेड डील लगभग पूरी हो चुकी थी। भारत को बातचीत फाइनल करने के लिए 'तीन शुक्रवार' का समय दिया गया था। लुटनिक ने कहा, ‘पूरी डील सेट थी, ट्रम्प खुद इसे क्लोज करना चाहते थे। इसके लिए बस मोदी को राष्ट्रपति को कॉल करना था। भारतीय पक्ष ऐसा करने में असहज था और मोदी ने कॉल नहीं किया।

वियतनाम और इंडोनेशिया से डील, भारत पीछे छूटा

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने खुलासा किया कि भारत के देरी करने का फायदा दूसरे देशों को मिला। उन्होंने कहा, 'हमने सोचा था कि भारत के साथ डील पहले होगी, लेकिन मोदी के कॉल न करने पर हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ ट्रेड डील कर ली।'

चांदी एक दिन में ₹4,168 महंगी हुई, ₹2.40 लाख पहुंची

सोने के दाम में ₹1,422 की तेजी, ₹1.37 लाख पार हुआ

नई दिल्ली, एजेंसी

सोने-चांदी के दाम में आज (9 जनवरी) तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,422 रुपए बढ़कर 1,37,195 रुपए पहुंच गया है। कल यह 1,35,773 रुपए/10g पर था। वहीं, एक किलो चांदी की कीमत 4,168 रुपए बढ़कर 2,39,994 रुपए पर आ गई है। कल इसकी कीमत 2,35,826 रुपए किलो थी। इससे पहले 29 दिसंबर 2025 को सोने की कीमत 1,38,161 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर थी। वहीं, चांदी की कीमत 7 जनवरी को 2,48,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई थी, जो इसके भाव का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। IBJA की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता। इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल यानी 2025 में सोने की कीमत 57,033 रुपए (75%) बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो 31 दिसंबर 2025 को 1,33,195 रुपए हो गया। चांदी का भाव भी इस दौरान 1,44,403 रुपए (167%) बढ़ा। 31 दिसंबर 2024 को एक किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो इस साल के आखिरी दिन 2,30,420 रुपए प्रति किलो हो गई।

तमसा संकेत

tamsa.news@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्यादेवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ- 226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित कराकर तमसा संकेत भवन शहजादपुर, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) (पिन कोड- 224122) से प्रकाशित

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।

मो0- 9415799533

R.N.I. NO. 64107/96